

श्रीलंका ने फिर पकड़े 7 भारतीय मछुआरे, नाव जब्त

नई दिल्ली/एजेंसी
श्रीलंका की नौसेना ने मंगलवार को कहा कि उसने देश के जलक्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने के आरोप में सात भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और उनकी नौका को जब्त कर लिया है। एक सप्ताह के भीतर मछुआरों को गिरफ्तार करने की यह दूसरी घटना है। नौसेना के प्रवक्ता ने बताया कि ये गिरफ्तारियां सोमवार रात को तलाईमन्नार क्षेत्र के जलक्षेत्र में की गईं। नौसेना ने बताया कि गिरफ्तार मछुआरों और उनकी नौका को मन्नार में मत्स्य निरीक्षणालय को सौंप दिया जाएगा। नौसेना ने रविवार को आठ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। भारत और श्रीलंका दोनों के मछुआरों को अक्सर अनजाने में एक-दूसरे के जलक्षेत्र में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मछुआरों का मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में एक विवादोत्पद विषय रहा है, जिसमें श्रीलंका की नौसेना के कर्मियों ने तो पाक जलडमरूमध्य में देश के जल क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने की कई कथित घटनाओं में भारतीय मछुआरों पर गोलीबारी तक की और उनकी नौकाओं को जब्त कर लिया था। पाक जलडमरूमध्य, तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाला एक संकरा जलक्षेत्र है, जो दोनों देशों के मछुआरों के लिए मछली पकड़ने के लिहाज से एक समृद्ध क्षेत्र है।

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवन ऐप को किया लॉन्च

नई दिल्ली/एजेंसी
रेल मंत्री ने CRIS के 40वें स्थापना दिवस समारोह में एक 'रेलवन' ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। रेलवन ऐप यात्रियों की सभी आवश्यक सेवाओं के लिए एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन है। इस ऐप के माध्यम से यात्रियों को निम्नलिखित सेवाओं तक सरलता से पहुंच मिलती है, टिकटिंग-आरक्षित, अनारक्षित, प्लेटफार्म टिकट; ट्रेन और डठफ पृष्ठताड,यात्रा योजना, रेल मदद सेवाएं, ट्रेन में भोजन बुकिंग. इसमें माल परिवहन (फ्रेट) से संबंधित पृष्ठताड की सुविधा भी उपलब्ध है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम



पहली बार स्टाफ के लिए आरक्षण नीति लागू

नई दिल्ली/एजेंसी
सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 75 साल के इतिहास में पहली बार स्टाफ के लिए आरक्षण नीति लागू की है। इसके तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के गैर न्यायिक पदों पर नियुक्तियों और प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलेगा। गैर न्यायिक पदों पर लागू हुआ आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नीति 23 जून 2025 को लागू हुई। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रशासनिक कामकाज में बड़े बदलाव का संकेत है। हालांकि जजों पर आरक्षण लागू नहीं होगा और सिर्फ रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी

नई खेल नीति पर केंद्र सरकार की मुहर

भारत को खेल महाशक्ति बनाना लक्ष्य, खेलों के जरिए राष्ट्रीय विकास और ओलंपिक 2036 की तैयारी की दिशा में बड़ा कदम

नई दिल्ली/एजेंसी

केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (एनएसपी-2025) लाई है जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाना है। एनएसपी-2025 वर्ष 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लेगी। इसका लक्ष्य नागरिकों को खेलों के माध्यम से सशक्त बनाना और भारत को 2036 ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन और आयोजन के लिए तैयार करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय खेल नीति-2025 को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि नीति व्यापक परामर्श के बाद तैयार की गई है, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, नीति आयोग, खेल संघ, खिलाड़ी और विशेषज्ञ शामिल रहे। नीति पांच प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खेल नीति-2025 के सफल क्रिया-व्यन के लिए एक ठोस रणनीतिक ढांचा तैयार किया गया है। इसमें सशक्त खेल प्रशासन के तहत खेलों के लिए मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा विकसित करने की योजना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए पीपीपी मॉडल



एनएच-87 के परमकुड़ी-रामनाथपुरम तक का खंड बनेगा चार लेन

नई दिल्ली। तमिलनाडु में एनएच-87 के परमकुड़ी से रामनाथपुरम तक के खंड को चार लेन का किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। निर्माण क्षेत्र की कुल लंबाई 46.7 किलोमीटर है और अनुमानित लागत 1,853 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय



कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में उक्त आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। केंद्रीय



मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। परियोजना

का उद्देश्य दक्षिणी तमिलनाडु के प्रमुख आर्थिक, सामाजिक और लॉजिस्टिक केंद्रों के बीच निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करना है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख रेलवे स्टेशन (मदुरै और रामेश्वरम), एक हवाई अड्डा (मदुरै) और दो छोटे बंदरगाह (पंबन और रामेश्वरम) को सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों और माल की तेज आवाजाही संभव हो सकेगी।

अनुरूप अपनी राज्य स्तरीय खेल नीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। खेलों के समग्र विकास के लिए एक समेकित सरकारी दृष्टिकोण अपनाया जाएगा, जिसमें सभी मंत्रालयों और विभागों की

और कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के माध्यम से वित्तीय सहयोग और समर्थन प्राप्त किया जाएगा।

नवाचार जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और अनुसंधान के जरिए खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और योजनाओं की निगरानी की जाएगी। नीति में एक राष्ट्रीय निगरानी ढांचा

भी प्रस्तावित है, जिसमें स्पष्ट प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई), लक्ष्य और समयबद्ध योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस नीति के

भारत के 'आकाश' का दिख रहा दबदबा

ब्राजील खरीद सकता है ये हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम

नई दिल्ली/एजेंसी
भारत की रक्षा क्षमताएं अब वैश्विक स्तर पर पहचान बना रही हैं। भारतीय हथियारों की तकनीक अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर सराही जा रही है। ब्राजील ने भारत की 'आकाश' वायु रक्षा प्रणाली और 'गरुड' तोपों में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी कि ब्राजील ने इन आधुनिक रक्षा उपकरणों सहित अन्य भारतीय प्रणालियों को हासिल करने



की इच्छा जताई है। यह बयान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन यात्रा से पहले आया है, जो अगले सप्ताह दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में होने जा रही है।

द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा
विदेश मंत्रालय में सचिव पी. कुमारन

ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि भारत और ब्राजील के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने पर गंभीर विचार किया जा रहा है।

उन्होंने बताया, "संयुक्त अनुसंधान, तकनीकी साझाकरण और प्रशिक्षण के अवसरों पर बातचीत चल रही है।

'व्यापार और सीजफायर से जुड़ी कोई बात नहीं हुई थी'

नई दिल्ली/एजेंसी

भारत-पाकिस्तान बीच हुए तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों देशों के बीच उन्होंने सीजफायर कराया था। अब इस दावे को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिर से खारिज कर दिया है। न्यूयॉर्क में न्यूजवीक को दिए इंटरव्यू में उन्होंने मई में भारत की ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के घटनाक्रम की पूरी कहानी बयां की है। जयशंकर ने बताया कि वह उस वक्त प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ कमरे में मौजूद थे, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फोन पर बात की थी। उन्होंने साफ कहा कि व्यापार



और सीजफायर से जुड़ी कोई बात नहीं हुई थी। भारत ने पाकिस्तान की धमकियों को टुकराते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। मैं उस वक्त कमरे में मौजूद था जब पीएम मोदी को अमेरिका उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया

था। इस दौरान व्यापार और सीजफायर को लेकर कोई बात नहीं हुई थी। जयशंकर ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 'आर्थिक युद्ध' बताते हुए कहा कि यह कश्मीर के पर्यटन को तबाह करने और धार्मिक

हिंसा भड़काने की साजिश थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि 9 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत पर बड़ा हमला किया, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। अगली सुबह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने जयशंकर से बात की और बताया कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है। उसी दिन दोपहर में पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिश अब्दुल्ला ने भारतीय समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चंड को फोन कर सीजफायर की गुजारिश की। विदेश मंत्री ने कहा, "मैंने खुद देखा कि क्या हुआ।"

डिजिटल इंडिया पहल के 10 साल पूरे, सरकार ने गिनाई उपलब्धियां

नई दिल्ली/एजेंसी

डिजिटल इंडिया मिशन के दस साल पूरे हो गए हैं। एक जुलाई 2015 को यह मिशन शुरू हुआ था। इसके दस वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत में अब 97 करोड़ से अधिक इंटरनेट कनेक्शन हैं, जो 2014 के 25 करोड़ से उल्लेखनीय वृद्धि है। उन्होंने देश में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी यात्रा और शासन, अर्थव्यवस्था और रोजगार की जिंदगी पर इसके व्यापक प्रभाव पर प्रकाश डाला।

इसके साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस डिजिटल इंडिया मिशन को डिजिटल क्रांति लाने वाला दूरदर्शी कार्यक्रम बताया। नड्डा ने एक्स पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया पहल के 10 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस दूरदर्शी कार्यक्रम ने पूरे देश में डिजिटल क्रांति ला दी है, एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है जिसने न केवल लाखों लोगों को जोड़ा है बल्कि नागरिकों के बीच डिजिटल विभाजन को भी पाट है।

मखाना को वैश्विक बाजार में मिलेगी अपनी विशिष्ट पहचान

नई दिल्ली/एजेंसी

बिहार के सुपरफूड मखाना को अंतरराष्ट्रीय स्तर का खास हमोनाईज्ड सिस्टम कोड मिल जाने से अब इसे वैश्विक स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में खेती होने वाले मखाना को अंतरराष्ट्रीय स्तर का खास एचएस कोड प्रदान किया गया है। इससे इस खास किस्म के जल फल को नई पहचान मिली है। इसे एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी



जा रही है। वर्षों के सतत प्रयासों के बाद मखाना उत्पादकों, प्रोसेसरों और उद्यमियों को अब उनका हक मिला है।

मखाना को वैश्विक बाजार में मिलेगी अपनी विशिष्ट पहचान मिथिलांचल खासकर दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया,

कटिहार समेत अन्य जिलों की खास पहचान यह मखाना है। इस कोड के मिलने से यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपने अलग नाम और हक से जाना जाएगा। इस कोड के मिलने से मखाना को वैश्विक बाजार में अपनी विशिष्ट पहचान मिलेगी, जिससे इसके व्यापार में पारदर्शिता और सहूलियत बढ़ेगी। मखाना को तीन विशिष्ट श्रेणी में बांटेकर इसके लिए एचएस कोड निर्धारित किए गए हैं।

राष्ट्रपति ने यूपी को दी पहले आयुष विश्वविद्यालय की सौगात

गोरखपुर/एजेंसी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय (विचि) का लोकार्पण किया। यह आयुष विश्वविद्यालय भट्टर क्षेत्र के पिपरी में 52 एकड़ क्षेत्रफल में बना है। इस विश्वविद्यालय के निर्माण में 267.50 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। राष्ट्रपति सोमवार से उत्तर प्रदेश के दो दिवसीय दौर पर हैं। आयुष विश्वविद्यालय के लोकार्पण अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि तपस्या साधना की धरती गोरखपुर राष्ट्रप्रेम की भी भूमि है। गोरखपुर धरती से जुड़ी महानविभूतियों को नमन करते हुए राष्ट्रपति ने गीता प्रेस का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मंदिर में पूजा-अर्चना करने के मौके पर कल गीता प्रेस की ओडिया भाषा में



मुझे शिव पुराण और भगवद्गीता पुस्तक भेंट की गयी। गीता प्रेस का योगदान बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करके हमें प्रसन्नता हो रही है। मुझे खुशी हो रही

है कि यहां उच्चस्तरीय सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। यहां आयुष पद्धतियों में स्नातक से लेकर उच्च स्तर का शिक्षण किया जाएगा। आयुष पद्धतियों से जुड़ी शिक्षा, पारम्परिक पद्धतियों के शोध कार्य पर

विशेष जोर दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने अथक और निद्राजीत का उल्लेख करते हुए कहा कि योगी बिना थके, बिना रुके कार्य कर रहे हैं। डाक्टर और नर्स को भी अथक और निद्राजीत बनना होगा। आप सब जीवनदायिनी हैं। आपको आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्या हम बेहतर कर पा रहे हैं। भारत योगी और ऋषियों की भूमि है। राष्ट्रपति ने कहा कि जल, थल, आकाश, वायु और अग्नि से मिलकर बना यह शरीर है। हमारे पास आज सारी सुविधाएं हैं। क्या यह सारी सुविधाओं का हमें उपयोग करना ठीक है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी के, उन्होंने योग का बढ़ावा दिया। आज भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। हम कहते हैं कि स्वास्थ्य ही संपदा है। भारत को विश्व गुरु

बनने के लिए हमें आज से ही प्रयास करना होगा। राष्ट्रपति ने आहार, विहार पर भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हमें स्वस्थ रहना है तो इलाज के साथ इसे भी अपनाना होगा। आयुर्वेद दवाओं की एक्सपायरी नहीं है। देश-विदेश की उपयोगी चिकित्सा पद्धतियों को 2014 के बाद देश और 2017 के बाद उग्र ने आयुष विभाग स्थापित कर अपनाया है। आयुष पद्धतियों की लोकप्रियता बढ़ रही है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विवि इसमें बहुत ही उपयोगी साबित होगा। राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि आयुष विवि खुलने से इलाज बेहतर होगा। साथ ही किसानों को भी फायदा होने वाला है। आयुर्वेद की दवाएं बनाने के लिए कई विशेष प्लांट चाहिए। वह खेत में ही होगा। इन दवाओं में केमिकल नहीं उपयोग किया जाएगा।

मनुष्य सोचने-समझने की शक्ति का इस्तेमाल सभी जीवों के कल्याण के लिए करे : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

एजेंसी
भरतपुर।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी प्रजातियों के संरक्षण को जैव विविधता और पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि ईश्वर ने मनुष्य को जो सोचने और समझने की शक्ति दी है उसका इस्तेमाल सभी जीवों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। श्रीमती मुर्मू ने सोमवार को बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) के दीक्षांत समारोह में कहा कि मनुष्य का वनो

और वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व का रिश्ता है। कई प्रजातियों के या तो विलुप्त होने या विलुप्त होने के कगार पर पहुंचने का उल्लेख करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि इन प्रजातियों का संरक्षण जैव विविधता और पृथ्वी के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ईश्वर ने मनुष्य को जो सोचने और समझने की शक्ति दी है, उसका उपयोग सभी जीवों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। कोरोना महामारी ने मानव जाति को आगाह

किया है कि उपभोग पर आधारित संस्कृति न केवल मानव जाति को बल्कि अन्य जीवों और पर्यावरण को भी अकल्पनीय नुकसान पहुंचा सकती है। राष्ट्रपति ने कहा कि 'ईशावास्यम् इदं सर्वम्' के जीवन मूल्य पर आधारित भारतीय संस्कृति सभी जीवों में ईश्वर की उपस्थिति देखती है। देवताओं और ऋषियों द्वारा जानवरों से संवाद करने की मान्यता भी इसी सोच पर आधारित है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि आज पूरे विश्व में 'एक स्वास्थ्य' की



अवधारणा को महत्व मिल रहा है। इसका मानना है मनुष्य, पालतू तथा जंगली जानवर, वनस्पतियां और व्यापक पर्यावरण सभी एक दूसरे

पर निर्भर हैं। हमें पशु कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख पशु चिकित्सा संस्थान के रूप में आईवीआरआई इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है खासकर जूनोटिक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण में। राष्ट्रपति ने कहा कि अन्य क्षेत्रों की तरह प्रौद्योगिकी पशु चिकित्सा और उनकी देखभाल में भी क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है। प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से देश भर के पशु चिकित्सालयों को सशक्त बनाया जा

सकता है। जीनोम एडिटिंग, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का उपयोग इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उन्होंने आईवीआरआई जैसे संस्थानों से पशुओं के लिए स्वदेशी और कम लागत वाले उपचार और पोषण खोजने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें उन दवाओं के विकल्प भी तलाशने चाहिए जिनके दुष्प्रभाव न केवल जानवरों बल्कि मनुष्यों और

पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। राष्ट्रपति ने मासूम और बेजुबान जानवरों के इलाज तथा कल्याण को अपना करियर चुनने के लिए आईवीआरआई के छात्रों की सराहना की। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि अपने जीवन और करियर में किसी दुविधा की स्थिति में जानवरों के बारे में सोचें। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें सही रास्ता मिलेगा। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से उद्यमी बनने और पशु विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्ट-अप स्थापित करने का आग्रह किया।

मौजूदा राजनीतिक माहौल लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं: उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़

बोधगया मंदिर बौद्धों को सौंपने की याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

एजेंसी
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बिहार के बोधगया मंदिर का नियंत्रण और प्रबंधन बौद्धों को सौंपने का निर्देश देने की मांग को लेकर प्रस्तुत याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने सुलेखाताई नलिनताई नारायणराव कुंभारे की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता नारायणराव को इस मामले में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी। अदालत ने याचिकाकर्ता को पटना उच्च न्यायालय से गुहार लगाने को कहा। न्यायमूर्ति सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सीधे विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी याचिका विचारणीय नहीं है। याचिकाकर्ता ने बोधगया मंदिर प्रबंधन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने और मंदिर का नियंत्रण और प्रबंधन बौद्धों को सौंपने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने संबंधित बोधगया मंदिर अधिनियम को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए कहा कि उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े चार पवित्र क्षेत्रों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि बोधगया वह स्थान है, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।



एजेंसी
नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर चल रहा है जिसमें राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति को भी घसीट लिया जाता है और यह भारतीय लोकतंत्र और संस्कृति से मेल नहीं खाता। श्री धनखड़ ने राजस्थान के जयपुर में राज्य के पूर्व विधायकों के संगठन राजस्थान प्रगतिशील मंच के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश का मौजूदा राजनीतिक परिवेश भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति से भी मेल नहीं खाता है। उन्होंने कहा, राजनीति में आप अलग-अलग दलों में हो सकते हैं और इसमें भी बदलाव होता रहता है। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष में जाता रहता है और प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष में आता रहता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि

दुश्मनी हो जाए। दरार पैदा हो जाए। दुश्मन सीमापार हो सकते हैं। देश में हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता।



उप राष्ट्रपति ने कहा कि राजनीति का परिवेश असहनीय हो रहा है। बेलगाम होकर वक्तव्य दिये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यापाल जब राज्य में होता है, तो उस पर आसानी से वार किया जा सकता है। राज्य की सरकार यदि केन्द्र की सरकार के अनुरूप नहीं है

तो आरोप लगना बहुत आसान हो जाता है। समय के साथ बदलाव आया और उपराष्ट्रपति भी इसमें जुड़

प्रजातंत्र में आवश्यकता है। उन्होंने कहा, अभिव्यक्ति हो, वाद-विवाद हो, संवाद हो। वैदिक तरीके से, जिसको अंततःवाद कहते हैं। अभिव्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण है और प्रजातंत्र की जान है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति कुठित होती है या उस पर कोई प्रभाव डाला जाता है या अभिव्यक्ति इस स्तर पर पहुँच जाती है कि दूसरे के मत का कोई मतलब नहीं है, तो अभिव्यक्ति अपना अस्तित्व खो देती है। अभिव्यक्ति को सार्थक करने के लिए वाद-विवाद को जरूरी करार देते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि दूसरे के मत को सुनना अभिव्यक्ति को ताकत देता है। सत्या, संतोष खोजने की अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें उन दवाओं के विकल्प भी तलाशने चाहिए जिनके दुष्प्रभाव न केवल जानवरों बल्कि मनुष्यों और पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं।

इस्पात उभरते भारत का आधार है :मोदी



एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुनियादी ढांचे और रक्षा क्षेत्र से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा स्वच्छ ऊर्जा तक इस्पात को उभरते भारत का आधार बताया है और कहा है कि नीतिगत प्रोत्साहन तथा नवाचार ने अपने लेख में बताया है कि कैसे सोमवार को सोशल मीडिया पर केन्द्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी का एक लेख साझा करते हुए कहा कि इसमें बताया गया है कि नीतिगत

प्रोत्साहन और नवाचार किस प्रकार से भारत को वैश्विक इस्पात क्षेत्र में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, बुनियादी ढांचे और रक्षा से लेकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और स्वच्छ ऊर्जा तक, इस्पात उभरते भारत का आधार है। केन्द्रीय मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने अपने लेख में बताया है कि कैसे नीतिगत प्रोत्साहन और नवाचार भारत को वैश्विक रूप से इस्पात क्षेत्र में अग्रणी बनाने की यात्रा को आकार दे रहे हैं।

तेलंगाना में रसायन फैक्ट्री में विस्फोट, छह की मौत, 20 घायल

एजेंसी
हेदराबाद। तेलंगाना में संगरेड्डी जिले में सोमवार सुबह एक केमिकल फैक्ट्री के रिफ़क्टर में विस्फोट होने से छह लोगों की मौत हो गयी और 20 अन्य घायल हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत नाजुक है। पुलिस ने बताया कि विस्फोट सिगाची इंडस्ट्रीज में हुआ। विस्फोट के कारण फैक्ट्री के कुछ हिस्सों में भीषण आग लग गयी। आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल की 11 गाड़ियाँ मौके पर पहुँचीं और आग पर काबू पाया। विस्फोट इतना जोरदार था कि कुछ कर्मचारी 100 मीटर दूर जाकर गिरे। फैक्ट्री प्रबंधन ने बताया कि घटना के समय करीब 30 कर्मचारी ड्यूटी पर थे। इस घटना में पांच श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य ने अस्पताल में दम तोड़ा। विस्फोट से फैक्ट्री के निर्माण और प्रशासनिक भवनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। घायलों को इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पताल ले

जाया गया। अधिकारियों ने आशंका जतायी है कि घायलों की हालत को देखते हुए मरने वालों की संख्या और



बढ़ सकती है। विस्फोट के बाद फैले रासायनिक धुएँ को देखते हुए पुलिस ने एहतियात के तौर पर आसपास के इलाकों को खाली करा दिया। संगरेड्डी कलेक्टर प्रवीण्या और पुलिस अधीक्षक परितोष घटनास्थल

पर राहत एवं बचाव कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रवंत

सुप्रीम कोर्ट पहुंच कोलकाता गैंगरेप का मामला, CBI जांच की उठाई गई मांग

एजेंसी
नई दिल्ली। कोलकाता गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट के वकील सत्यम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही, उन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की मांग की गई है, जो इस मामले को लेकर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। वकील सत्यम सिंह ने अपने पत्र में पीठिता को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और उसके परिवारों को सुरक्षा देने की मांग की है। इसके अलावा, शैक्षणिक संस्थानों में व्यापक सुरक्षा उपाय, जिनमें अनिवार्य सीसीटीवी निगरानी, महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ और नियमित सुरक्षा ऑडिट शामिल हैं, की मांग की गई है। वहीं, वकील ने अपने पत्र में पश्चिम बंगाल में यौन अपराधों के खिलाफ कानूनों को मजबूत करने के लिए अपराजिता विधेयक को तुरंत लागू किए जाने की मांग की है।

याचिका में पश्चिम बंगाल में पेशेवरों, खासकर महिला वकीलों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए सीबीआई जांच, सुरक्षा प्रोटोकॉल और संस्थागत सुधारों की मांग की गई है। याचिका में पीठिता के लिए



न्याय के साथ-साथ कानूनी बिरादरी की सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था की अखंडता सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। 25 जून को कोलकाता के लॉ कॉलेज में एक स्टूडेंट के साथ गैंगरेप किया गया था। इसमें तीन आरोपी शामिल थे। तीनों ही छात्र इसी कॉलेज के थे। इनमें इसमें एक आरोपी कॉलेज का पूर्व छात्र है, जो टीएमसी से जुड़ा बताया

जा रहा है, जिसे लेकर भाजपा टीएमसी पर हमलावर है। हालांकि, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर देशभर में आक्रोश है। सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच, टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा ने इस सामूहिक दुष्कर्म मामले में विवादित टिप्पणी की है। कल्याण बनर्जी ने कहा था, अगर दोस्त ही दोस्त का रेप करे, तो क्या किया जा सकता है? क्या स्कूलों और कॉलेजों में हर जगह पुलिस तैनात की जा सकती है? मदन मित्रा ने भी इस मामले में विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर पीठिता किसी को सूचित करती या दोस्तों को साथ ले जाती, तो यह टल सकता था। वहीं, इस संवेदनशील मामले में विवादित टिप्पणी करके मदन मित्रा मुश्किलों में घिर गए हैं। ममता बनर्जी ने उन्हें इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करके तीन दिन में जवाब तलब किया है।

बिहार में 2003 की मतदाता सूची के 4.96 करोड़ मतदाताओं को सबूत देने की जरूरत नहीं

एजेंसी
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाया है और उसमें शामिल 4.96 करोड़ मतदाताओं को समीक्षा के दौरान अपनी पहचान के सबूत के तौर पर कोई दस्तावेज जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि वर्ष 2003 की मतदाता सूची उसकी वेबसाइट पर अपलोड की गयी है जिसमें 4.96 करोड़ मतदाताओं के विवरण शामिल हैं। आयोग ने कहा कि इस सूची के मतदाताओं को

समीक्षा के दौरान कोई दस्तावेज नहीं देना होगा तथा इनके बच्चों को अपने

माता-पिता से संबंधित कोई दस्तावेज जमा कराने की भी जरूरत नहीं है। आयोग ने कहा इस वर्ष होने जा रहे राज्य विधान सभा चुनावों से पहले बृथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को घर-घर भेज कर सूचियों की विशेष गहन समीक्षा कराने का अभियान शुरू किया है।

आयोग ने गत सप्ताह मंगलवार 24 जून के आयोग के निर्देशों के पैरा 5 में उल्लेख किया गया था कि सीईओ/डीईओ/ईआरओ 01.01.2003 की अर्हता तिथि वाली मतदाता सूची को सभी बीएलओ को हार्ड कॉपी में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराएँ, साथ ही अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध कराएँ, ताकि कोई भी व्यक्ति इसे डाउनलोड कर सके और अपना गणना फॉर्म जमा करते समय दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में उपयोग कर सके। आयोग का कहना है,वर्ष 2003 की मतदाता सूची सामने होने से विशेष गहन पुनरीक्षण में काफी सुविधा होगी क्योंकि अब कुल

मतदाताओं में से लगभग 60 प्रतिशत को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। उन्हें केवल नामावली में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से अपने विवरण को सत्यापित करना होगा और भरा हुआ गणना फॉर्म जमा करना होगा। मतदाता और बीएलओ दोनों ही इन विवरणों तक आसानी से पहुँच सकेंगे। आयोग के निर्देशों के अनुसार,कोई भी व्यक्ति जिसका नाम वर्ष 2003 की बिहार मतदाता सूची में नहीं है, वह अभी भी अपने माता या पिता के लिए कोई अन्य दस्तावेज प्रदान करने के बजाय वर्ष 2003 की मतदाता सूची के संबंधित हिस्से (अंश) का उपयोग कर सकता है।

अगर हिंदी थोपने के फैसले को वापस नहीं लेती सरकार तो 5 जुलाई को दिखती एकता : उद्धव ठाकरे

एजेंसी
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार की त्रिभाषी नीति को वापस लिए जाने पर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदी थोपने वाला सरकारी आदेश वापस नहीं किया गया होता, तो 5 जुलाई की रैली में भाजपा, शिंदे गुट और अजित पवार गुट के लोग भी शामिल होते। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार के साथ आएँ करते हुए कहा, 'रिवार को, 'जय महाराष्ट्र' का नारा हर जगह गूंज उठा। सभी दल जो दलीय मतभेदों को भूलकर शिवसेना के साथ आएँ। अगर हिंदी थोपने वाला आदेश वापस नहीं लिया गया होता, तो भाजपा, शिंदे गुट और अजित पवार गुट के लोग

भी 5 जुलाई की रैली में शामिल होते। मातृभाषा के प्रति प्रेम किसी भी पार्टी से ऊपर होना चाहिए। उन्होंने कहा, नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। सरकार को



इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एक अर्थशास्त्री को शिक्षा समिति में रखा गया है। मैं इतना ही अध्यक्षता कि अब सरकार को हिंदी को जबरन थोपने के लिए कोई और कदम नहीं उठाना चाहिए।

पंजाब पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का किया भंडाफोड़, 60 किलो हेरोइन बरामद

अमृतसर। पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास से 60.302 किलोग्राम हेरोइन को बड़ी खेप बरामद की गई। इस कार्टेल को पाकिस्तानी तस्कर तनवीर शाह और कनाडा में रहने वाला हैंडलर जोबन कलेर संचालित कर रहा था। पंजाब पुलिस ने इस ऑपरेशन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर से नौ प्रमुख तस्करों और हवाला ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया। इन गिरफ्तारियों ने ड्रग तस्करों के इस विशाल नेटवर्क की कमर तोड़ दी, जो न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सक्रिय था।

एजेंसी
नई दिल्ली। कांग्रेस ने पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भगदड़ में श्रद्धालुओं के हाताहत होने को अत्यंत गंभीर घटना बताते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा है कि घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। कांग्रेस सांसद ससर्गिर

उल्लाका तथा पार्टी नेता अरविंद दास ने सोमवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में इसे राज्य की भाजपा सरकार को कुप्रबंधन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि इस पवित्र कार्यक्रम में वीआईपी पर ध्यान केंद्रित करने के कारण उससे जो चूक हुई है, उसके लिए भाजपा सरकार प्रभु

जगन्नाथ से माफी मांगे और आश्वासन दे कि भविष्य में इस तरह की चूक नहीं होगी। सरकारी तंत्र सिर्फ वीआईपी की सेवा में नहीं रहेगा और प्रभु के आम भक्तों की सुरक्षा पर भी सतर्क रहेगा। उन्होंने भगदड़ की घटना के लिए मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री को जिम्मेदार बताते हुए इस्तीफे की

मांग करते हुए कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की मदद करने करने और गंभीर रूप से घायलों को 25-25 लाख रुपए की सहायता देने की भी मांग की है। उन्होंने रथ यात्रा में कुप्रबंधन के कारण इस तरह की घटनाओं को

शर्मनाक बताया और कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि आगे से इस तरह की घटनाएँ नहीं हों। उनका कहना था कि पिछले साल 'प्रभु बलभद्र' जो की मूर्ति भी गिरा दी गई थी। तब सरकार ने कहा था कि इस मामले की जांच की जाएगी लेकिन आज तक इसमें कुछ सामने नहीं आया है। असलियत यह है कि

भाजपा सरकार ने रथ यात्रा को 'इवेंट मैनेजमेंट' में बदल दिया है जिसके कारण यह गंभीर चूक हुई है। घटना की जवाबदेही तय होनी चाहिए।कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ओडिशा के बाहर से भी बड़ी संख्या में लोग इस क्षेत्र में आने लगे हैं और उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है।

ट्रक चालकों की हत्या में शामिल एक लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में डेर

एजेंसी नई दिल्ली। बागपत में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की नोएडा यूनिट और बागपत पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में रविवार रात बागपत के थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। उसे तत्काल उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक बदमाश की पहचान संदीप (35) निवासी धौगो महाराजगंज थाना महम जिला रोहतक हरियाणा के रूप में हुई है। आरोपी इस वर्ष कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र में ट्रक से चार करोड़ रुपए का सामान निकल प्लेट (स्टील की धातु) लूट के मामले बांछित चल रहा था। इस सनसनीखेज वारदात के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था। एसटीएफ नोएडा यूनिट के अपर पुलिस अधीक्षक राज कुमार मिश्र ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर चेकिन के दौरान आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि संदीप एक शक्तिर हाईवे लुटेरा था। वह अब तक चार से अधिक ट्रक ड्राइव्स की हत्या कर करोड़ों रुपये के माल से लदे ट्रक लूट चुका है।

‘इसे चाकू मार दो’ : बेटे को डांट रहा था पिता, दोस्त के कहने पर कर दिया कत्ल, फिर खुद लेकर पहुंचा अस्पताल

नई दिल्ली। सागरपुर इलाके में बात मानने से इनकार करने पर एक पिता ने अपने 10 साल के बेटे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। चाकू मारने के बाद आरोपी घायल बेटे को लेकर खुद ही अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल ने बताया कि सागरपुर थाना पुलिस को घटना के बारे में जानकारी मिली। दादा देव अस्पताल पहुंची पुलिस को पता चला कि बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मुतक की शिनाख्त 10 साल के शिवा के रूप में हुई। जांच में पता चला कि शिवा अपने पिता ए रॉय पेंटर का काम करते हैं। वहीं, बहन घरेलू सहायिका है। कुछ साल पहले उसकी मां की मौत हो गई थी। परिवार मूलतः असम का रहने वाला है। रविवार को बारिश हो रही थी। शिवा के पिता अपने एक दोस्त के साथ घर पहुंचे। आरोप है कि आरोपी पिता नशे में था। जिस समय वह घर पहुंचा, शिवा बारिश में भीग रहा था और घर के बाहर उछल-कूद कर रहा था। पिता ने उसे घर आने के लिए कहा, लेकिन शिवा उनकी बातों को अनसुना कर दिया।

फैक्टरी की छत से गिरकर मजदूर की मौत, रात में साथियों के साथ, सोने गया शिवम

एजेंसी नई दिल्ली। टूनिंका सिटी थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर-डी एक स्थित धागा बनाने की फैक्टरी की छत से गिरने पर शनिवार रात मजदूर शिवम तिवारी (24) की मौत हो गई। मजदूर अन्य साथियों के साथ सोने के लिए फैक्टरी की छत पर गया था। सुबह मजदूर फैक्टरी के बाहर में जमीन पर पड़ा हुआ मिला। परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से शिकायत की है। मूलरूप से इटाली के बरथना थाना क्षेत्र में रहने वाले शिवम तिवारी टूनिंका सिटी औद्योगिक क्षेत्र स्थित धागा बनाने की फैक्टरी में काम करते थे। वह फैक्टरी में रहते थे। उनकी चाची रंजना ने बताया कि उन्हें सूचना दी गई कि उनके भतीजे शिवम तिवारी का एक्सिडेंट हो गया है। सूचना पाकर वह मौके पर पहुंची। मौके पर आकर पता चला कि शिवम तिवारी की छत से गिरने पर मौत हुई है। आरोप है कि जिस फैक्टरी से गिरने पर उनके भतीजे की मौत हुई है, उस फैक्टरी से हटा कर उनके भतीजे के शव को दूसरी फैक्टरी में लाया गया है। उन्होंने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस से की है।उन्होंने मांग की है कि उनके भतीजे को अगर किसी ने मारा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने मामले में पुलिस को शिकायत दी है। एसीपी लोनी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि शिवम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर मौत के कारण का पता चलेगा।

दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बरसे बरसा, तपती गर्मी से लोगों को मिली राहत

नई दिल्ली। गुरुग्राम, नोएडा समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज फिर बारिश देखने को मिली। इस पहले शनिवार दोपहर को दिल्ली-एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में हुई बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दिलाई है। इससे पारा भी सामान्य से नीचे चला गया। दोपहर तक खिली धूप के कारण लोग गर्मी से परेशान थे। दोपहर बाद काले बादल छा गए, जिसके बाद कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने रविवार के लिए यलो अलर्ट जारी किया था। साथ ही उम्मीद जताई है कि दो जुलाई तक दिल्ली में बारिश हो सकती है। गुरुग्राम में रुक-रुक कर हो रही बारिश ने उमस से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक और बारिश होने की संभावना जताई है। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर का मौसम सुखवना हो गया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। जिससे वातावरण में उडक बनी हुई है।

दिल्ली विस अध्यक्ष धर्मशाला में आयोजित दो दिवसीय वार्षिक विधायक सम्मेलन में लेंगे भाग

एजेंसी नई दिल्ली । दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता धर्मशाला में आयोजित दो दिवसीय वार्षिक विधायक सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका आयोजन 30 जून एवं 1 जुलाई को किया जाएगा। यह दो दिवसीय सम्मेलन दिल्ली, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर एवं पंजाब विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों एवं विधायकों को एक मंच पर लाकर विधायी सुशासन, लोकतांत्रिक उन्नतवियल और अंतर-राज्यीय सहयोग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी रविवार को एक विज्ञित जारी करके दी गई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष के साथ जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, मुख्य सचेतक अभय वर्मा, विधायक शिखा राय एवं जितेंद्र महजन, तथा दिल्ली विधान सभा के सचिव रंजीत सिंह शामिल हैं। इस सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। सम्मेलन में सविधान विशेषज्ञों, सांसदों, विधायकों एवं वरिष्ठ संसदीय अधिकारियों की सहभागिता होगी। इसका उद्देश्य बदलते सामाजिक-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में संसद एवं विधानसभाओं की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावशाली एवं सुदृढ़ बनाने पर संवाद को बढ़ावा देना है। सम्मेलन के मुख्य विषयों में राज्य संसाधनों के प्रबंधन में विधायिकाओं की भूमिका तथा राज्य के समग्र विकास में उनके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के उपाय शामिल हैं। इस सत्र में यह चर्चा होगी कि कैसे विधायिकाएं जवाबदेह शासन सुनिश्चित कर सकती हैं, वित्तीय अनुशासन बनाए रख सकती हैं और विकास के लक्ष्यों को जलजित से जोड़ सकती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण विषय होगा दलबदल के आधार पर विधायकों की अयोग्यता से संबंधित संवैधानिक प्रवधान, जो सविधान के अनुच्छेद 102(2) और 191(2) के अंतर्गत दसवीं अनुसूची में वर्णित हैं। यह सत्र दलबदल विरोधी कानून की पवित्रता को बनाए रखने की वतमान चुनौतियों एवं पीठासीन अधिकारियों द्वारा समयबद्ध और निष्पक्ष निर्णय लेने की आवश्यकता में अस्पताल लाया गया है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो पता चला कि बच्चा मृत अवस्था में था और उसे खुद उसके पिता लेकर आए थे। मृतक बच्चे की पहचान शिवम (10) के रूप में हुई है। वह अपने पिता ए रॉय (40) और तीन भाई-बहनों के साथ सागरपुर के मोहन ब्लॉक इलाके में एक छोटे से कमरे में रहता था। बच्चे की मां का निधन कुछ साल पहले हो गया था। प्राथमिक जांच में सामने आया कि बच्चा बारिश में खेलने की जित कर

दिल्ली हाट आईएनए अग्निकांड में प्रभावित शिल्पकारों के लिए पांच-पांच लाख रुपये की राहत की घोषणा

एजेंसी नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली हाट आईएनए अग्निकांड में प्रभावित शिल्पकारों के लिए पांच-पांच लाख रुपये की राहत की घोषणा की है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि 30 अप्रैल की देर शाम दिल्ली हाट आईएनए में आग लगने की घटना में 24 स्टॉल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गए। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रत्येक प्रभावित शिल्पकार को पांच-पांच लाख रुपये की राहत राशि देने की घोषणा की गई है। कपिल मिश्रा ने बताया कि पांच-



पांच लाख रुपये की अनुग्रह राहत राशि को मंजूरी दी जा चुकी है और कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि 24 प्रभावित शिल्पकारों को

कपिल मिश्रा ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को किसानों के साथ सुना

एजेंसी नई दिल्ली। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आज लग्गारा स्टोडियम में किसानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। यह जानकारी उन्होंने एक्स पर साझा की। उन्होंने पोस्ट करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री ने चिरंजीवी योग परंपरा, आपातकाल की चेतावनी, पेड़ लगाने के संकल्प जैसे अलग-अलग विषयों पर राष्ट्र से संवाद किया। प्रधानमंत्री के सुंदर विचारों को सुनना, गुनना और जीवन में उतारना यही संकल्प सम्पूर्ण राष्ट्र का है ताकि जीवन को हर मायने में विस्तार मिल सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि दिल्ली पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित तीन दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया था। इससे पहले आज कपिल मिश्रा

गंभीरता से सुनकर तुरंत समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि करावल नगर

के हर परिवार, हर मोहल्ले का सुख-दुख उनका अपना है और इसी अपनापन से वो हमेशा आपके बीच खड़े मिलेंगे।

उन्होंने हर एक व्यक्ति की बात को

झुगियां तोड़ने के विरोध में आआपा का प्रदर्शन, भाजपा ने बताया फ्लॉप, कांग्रेस बोली- घड़ियाली आंसू बहा रही आआपा

एजेंसी नई दिल्ली। दिल्ली में झुगियां तोड़ने के विरोध में आम आदमी पार्टी (आआपा) ने जंतर-मंतर पर घर-रोजगार बचाओ आंदोलन के तहत जनसभा का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, सांसद संजय सिंह, दिल्ली संयोजक सोरभ भारद्वाज समेत पार्टी के अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मैंने चेतावनी दी थी कि अगर भाजपा सत्ता में आई, तो एक साल के भीतर झुगियां उजाड़ दी जाएंगी। लेकिन इन लोगों ने तो 2-3 महीनों में ही झुगियां को तोड़ डाला और गरीबों के सिर से छत छीन ली। केजरीवाल ने दावा

किया कि दिल्ली में 40 लाख से ज्यादा झुगियावासी हैं और अब वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।



उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर झुगियां तोड़ना बंद नहीं किया गया, तो सत्ता का सिंहासन डोलने में देर नहीं लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा, मोदी जी ने वादा किया था - जहां झुगी, वहां मकान, लेकिन

कॉंग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, कांग्रेस के शासन में भी झुगियां तोड़ी गईं। जब पांडव नगर की झुगियां तोड़ी जा रही थीं, तब मैंने और मनीष सिंसोदिया ने विरोध किया था। ये पार्टियां केवल अमीरों के लिए काम करती हैं, गरीबों के

ग्रेटर नोएडा में कॉलेज के बाहर तीन कारों से खतरनाक स्टंट, भाजपा झंडा लगी गाड़ी भी शामिल

एजेंसी नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिम जिले के सागरपुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक पिता ने बारिश में खेलने की जित कर रहे अपने 10 वर्षीय बेटे की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के अनुसार, दोपहर करीब 1:30 बजे दादा देव अस्पताल से एक पीसीआर कोल थाना सागरपुर को मिली। जिसमें बताया गया कि एक बच्चा चाकू लगने से घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो पता चला कि बच्चा मृत अवस्था में था और उसे खुद उसके पिता लेकर आए थे। मृतक बच्चे की पहचान शिवम (10) के रूप में हुई है। वह अपने पिता ए रॉय (40) और तीन भाई-बहनों के साथ सागरपुर के मोहन ब्लॉक इलाके में एक छोटे से कमरे में रहता था। बच्चे की मां का निधन कुछ साल पहले हो गया था। प्राथमिक जांच में सामने आया कि बच्चा बारिश में खेलने की जित कर

राजद नेता चंद्रशेखर यादव का आरोप, ‘मतदाताओं को वोट लिस्ट से निकालने की रची जा रही साजिश’

एजेंसी नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए वोट लिस्ट मेगा वरिफिकेशन अभियान पर विपक्षी दलों ने संदेह व्यक्त किया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और इंडिया ब्लॉक के नेता इसे गरीब, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की साजिश करार दे रहे हैं। चंद्रशेखर यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है। राजद नेता चंद्रशेखर यादव ने समाचार एजेंसी से बातचीत की। उन्होंने कहा, कम समय में इतने बड़े पैमाने पर वरिफिकेशन संभव नहीं है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। एक जून तक सत्यापन पूरा हो जाने के बाद, उन्हें अचानक गहन पुनः सत्यापन की आवश्यकता महसूस हुई। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी घृणास्पद, सांप्रदायिक रणनीति अब समाज को धोखा नहीं दे रही है। बिहार हमेशा से बदलाव की भूमि रहा है और हमेशा नफरत के खिलाफ खड़ा रहा है। इसे देखते हुए, उन्होंने लगातार सर्वेक्षण करना शुरू कर दिया। इसमें संघ और भाजपा दोनों शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जब तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे युवा नेता गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मूल मुद्दों पर लोगों तक पहुंचते हैं, तो उनके लिए जनता का समर्थन बढ़ता है। इससे नफरत फैलाने वाली ताकतें घबर गई हैं, और उन्हें अपनी जमीन खोने का डर सता रहा है।

युवक ने फंदा लगाकर की खुदकुशी

एजेंसी नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के वसंतकुंज नार्थ स्थित मसूदपुर गांव में शनिवार शाम एक युवक ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक की शिनाख्त गांव पिलशी, बसियूं, उत्तर प्रदेश निवासी उदयभान (23) के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। उसका भाई काम से लौटा तो उसने देखा कि भाई पंखे पर मफलर के सहारे फंदे से लटका है। उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। युवक को फंदे से उतारकर सपरदरज अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद उदयभान का शव परिवार के हवाले कर दिया है। पुलिस उसके परिजनों से पूछताछ कर आत्महत्या की वजहों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। निर्माण कार्य चल रहा है। भाई ने उसे यहां काम लिखा दिया था। फिलहाल उसकी रात की शिफ्ट चल रही थी।

अवैध सिगरेट का गोदाम पकड़ा, 94 हजार पैकेट जब्त, दो तस्क़र गिरफ्तार

एजेंसी नई दिल्ली। दक्षिण-पश्चिम जिले की ऑपरेशंस सेल टीम ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए वसंत कुंज के नंगल देवत इलाके में स्थित एक अवैध सिगरेट के गोदाम का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 94,000 पैकेट बिना वैधानिक चेतावनी और एमआरपी के विदेशी सिगरेट जब्त की हैं। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपितों की पहचान वसंत कुंज निवासी परशित (22) और कर्नाटक निवासी पी.पी. चेंगप्पा (40) के रूप में हुई है। दक्षिण-पश्चिम जिले के डीसीपी अमित गोयल के अनुसार जिले की पुलिस द्वारा तंबाकू उत्पादों के अवैध व्यापार के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ऑपरेशंस सेल की टीम को सूचना मिली कि नंगल देवत क्षेत्र में एक मकान के बेसमेंट में विदेशी सिगरेट का अवैध स्टॉक जमा किया गया है, जो दिल्ली-एनसीआर और दक्षिण भारत में सप्लाई की जानी है। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छपा मारा और उपरोक्त दोनों आरोपितों को मौके से गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में विदेशी सिगरेट जब्त की गई। बरामद सिगरेट में एलएडबी ओरिजिनल सिल्वर - 13 कार्टन (13,000 पैकेट), किंग साइज मेफेयर 5 कार्टन (5,000 पैकेट), रिचमंड किंग साइज रियल ब्लू - 50 कार्टन (50,000 पैकेट) और रिचमंड किंग साइज - 26 कार्टन (26,000 पैकेट) शामिल हैं। डीसीपी के अनुसार जांच में पता चला है कि पकड़ा गया आरोपित परशित वसंत कुंज का रहने वाला है। उसके पिता एयरपोर्ट पर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम करते हैं। परशित ने पहले अपने पिता से काम सीखा और बाद में स्वतंत्र रूप से कारोबार करने लगा।

अचानक ब्रेक लगाकर वाहन को रोकता है। इसी दौरान ब्रेजा में सवार एक युवक खिड़की से बाहर निकलकर हथ लहराता हुआ दिखता है। दूसरी कार जो बलेंगे है। उसमें बैठ एक युवक खिड़की से डंडा बाहर निकालकर लहराता हुआ नजर आता है। तीसरी कार को चालक

पर्यावरण मंत्री ने नेहरू पार्क का दौरा कर वलीन एयर जोन बनाने की संभावना का किया अध्ययन

एजेंसी नई दिल्ली। दिल्ली की वायु गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए वैज्ञानिक उपायों की दिशा में एक बड़ा कदम उठते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और लोक निर्माण विभाग के मंत्री व क्षेत्रीय विधायक प्रवेश साहिव सिंह ने आज नेहरू पार्क का दौरा किया। उन्होंने भविष्य 'क्लीन एयर जोन' बनाने की संभावना का अध्ययन किया। यह पहल दिल्ली का पहला 'क्लीन एयर जोन' बनने की दिशा में एक शुरुआती अध्ययन का हिस्सा है। 85 एकड़ में फैले इस पार्क को पायलट साइट के रूप में देखा जा रहा है, जहां 150 एडवांस एयर प्यूरिफायर लगाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। इन मशीनों को पहले आईएसबीटी, पेट्रोल पंपों और अन्य स्थानों पर टेस्ट किया गया है, जहां इन्होंने सीमित क्षेत्र में पीएम 2.5 स्तर को घटाने में अच्छे नतीजे दिए। निरीक्षण के दौरान पर्यावरण विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और लोक निर्माण विभाग के

कोलकाता गैंगरेप केस : भाजपा सांसद सबित पात्रा ने ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा

एजेंसी नई दिल्ली । कोलकाता सामूहिक बलात्कार मामले पर सियासत तेज हो गई है। इस जघन्य घटना को लेकर भाजपा सांसद सबित पात्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री हैं, वहां इस तरह की घटनाएं

होना कहीं न कहीं उनकी विफलता का प्रमाण है। भाजपा सांसद ने कहा, =हम (मुख्यमंत्री) ममता बनर्जी से स्पष्टीकरण नहीं मांग रहे हैं। हम उनसे माफ़ी मांगने और इस्तीफा देने के लिए कह रहे हैं। वह जल्द से जल्द इस्तीफा सौंपें। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री हैं,

वहां महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए। इतनी असंवेदनशील और क्रूरता क्यों है? पीड़िता ने खुद बयान जारी किया है। अगर इसे ध्यान से पढ़ें तो एक बात साफ हो जाती है कि गैंगरेप का यह पूरा दुष्प्रक्र कहीं न कहीं राज्य प्रायोजित है। यह राजनीतिक दृष्टिकोण

से प्रेरित एक क्रूर कृत्य है क्योंकि यह एक कॉलेज के छात्र संघ से जुड़ा है, जिसका मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा है। भाजपा सांसद ने कहा कि मनोजीत मिश्रा खुद तुणमूल कांग्रेस की छात्र शाखा का सचिव रह चुका है। वह तुणमूल कांग्रेस का सदस्य है। पात्रा ने कहा कि ममता

बनर्जी बलात्कार के इन सभी क्रूर मामलों को बहुत हल्के में लेती हैं। सांसद कल्याण बनर्जी के बयान को ही देख लीजिए। वह कहते हैं कि अगर दोस्त ही दोस्त का बलात्कार करे तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार यह कह रही है कि वह कुछ नहीं कर सकती। सबित पात्रा ने शनिवार को दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गेरेप की पीड़िता का वह पत्र भी पढ़कर सुनाया, जिसमें उसने कहा कि उसके साथ शाम 7-30 बजे से लेकर रात 10-30 बजे तक गैंग रेप हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने एक कमटी बनाई है जो मौके पर जाकर जांच करेगी। इसके सदस्य पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्पाल सिंह, मोनाक्षी लेखी और सांसद बिप्लव देव तथा मनन मिश्रा हैं। यह कमटी जल्द ही मौके का दौरा कर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपेगी।

संपादक की कलम से

बेलग्रेड का आंदोलन!.. भारत ठंडा-ठंडा!!

भारतीय लोकतंत्र मानो बिना पैसे का एक तमाशा बन गया है। लोगों के वोटों पर चुनकर आना और सत्ता भोग करना। फिर उन्हीं लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को नष्ट कर देना। मौजूदा शासक लोगों के आंदोलनों को कुचलने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अपने ही लोगों से डरकर दमनकारी शक्ति का रास्ता अख्तियार करनेवाली वर्तमान सरकार को लोकतंत्र का एक अजब नमूना कहा जाना चाहिए। यस पृष्ठभूमि में लोकतंत्र के प्रति दुनिया की जागरूकता महत्वपूर्ण है। छोटे से देश बेलग्रेड में लाखों लोग अपने राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक के इस्तीफा के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। नोबी सैंड रेलवे स्टेशन पर एक शेड गिरने से हुई दुर्घटना में १६ नागरिकों की मौत हो गई। लोग निर्माण में भ्रष्टाचार को इस दुर्घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है। इस देश की आबादी केवल सवा तेरह लाख ही है और उनमें से कम से कम दस लाख लोग कई शहरों में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध १ नवंबर २०२४ को शुरू हुआ था। इस आंदोलन ने प्रधानमंत्री मिलोस वुसेविक और परिवहन मंत्री गोरान वुसेक को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया, लेकिन लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति वुसिक इस्तीफा दें। राष्ट्रपति वुसिक के समय में हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार बढ़ा है। वह अपने चहेते लोगों को सरकारी ठेके देते हैं और इसके खिलाफ आवाज उठानेवालों को किसी न किसी तरह से परेशान करते हैं। राष्ट्रपति वुसिक लोकतंत्र का गला घोटकर शासन कर रहे हैं इसलिए लोग सड़कों पर उतर आए और संघर्ष शुरू कर दिया। लोगों ने सड़कें जाम कर दीं, ट्रेंनें रोक दीं, स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए। नोबी सैंड में सत्तारूढ़ पार्टी सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी के कार्यालय पर अंडे फेंके गए। इस विरोध का मूल नोबी सैंड ट्रेन स्टेशन पर हुई दुर्घटना में निर्दोष लोगों की मौत है। भारत में ऐसे मामलों में हुक्मरानों की बेशर्मी साफ झलकती है। भ्रष्टाचार, दुर्घटनाओं और उससे होनेवाली मौतों को लेकर सरकार बेशर्मी भरा व्यवहार करती है। कश्मीर घाटी के पहलगाम में आतंकवादियों ने २६ पर्यटकों को मार डाला। देश के गृह मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने एक कमजोर छाऑपरेशन सिंदूरूह शुरू किया और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध रोक दिया गया। २६ पर्यटकों के बलिदान की जिम्मेदारी किसी लेनी चाहिए? इससे पहले पुलवामा हमले में ४० सैनिकों की हत्या के बावजूद, सरकार ने न तो माफी मांगी और न ही इस मामले पर विपक्ष के विचारों को समझा। सर्बिया में एक पुल गिरने के कारण प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। बिहार और महाराष्ट्र में पिछले साल १७ पुल ढह गए। मावल जिले में इंद्रायणी पर एक पुल गिरने से चार लोगों की मौत हो गई। यह सब भ्रष्टाचार के कारण हुआ। जब से अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने हैं, तब से भयानक रेल दुर्घटनाओं का सिलसिला चल रहा है। रेल दुर्घटनाओं में अनगिनत लोग मारे गए हैं, लेकिन देश के रेल मंत्री ने अपनी कुर्सी छोड़ने की विनम्रता और ईसानियत नहीं दिखाई। मुंबई उपनगरीय रेल दुर्घटनाओं के आंकड़े चिंताजनक हैं। २०१४ से २०२४ तक पिछले १० सालों में रेल दुर्घटनाओं में ३६,७०० लोगों की मौत हुई है। इनमें से १२,३०० शवों की पहचान भी नहीं हो पाई है। यह हकीकत भयावह है। हमारे देश में दुर्घटना के बाद लोग सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन फिर सब कुछ ठंडा और ठंडा पड़ जाता है। अमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें २४७ लोग मारे गए। यह दुर्घटना संधिध है। क्या भारत सरकार में कोई हमाई का लालहू है, जो इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी ले सके? इस कमनसीब लोकतंत्र को हम क्या कहे? राष्ट्रपति ट्रंप की प्रशासन की मममानी के खिलाफ पूरे अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इजरायल में लोगों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू की युद्धेन्माद के खिलाफ आवाज उठाई है। पड़ोसी बांग्लादेश में सरकार उखाड़ दी गई। श्रीलंका में भी जनता ने विद्रोह कर दिया। म्यांमार में भी सैन्य शासन के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन भारत में लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे क्रूर उपाय लागू किए जाते हैं। जब शिक्षकों, छात्रों और शिक्षित युवाओं के आंदोलन को बलपूर्वक कुचला जाता है और यही लोग फिर से आपातकाल के नाम पर गला फाड़ते हैं तो इस बात की तस्वीक हो जाती है कि भारत में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र में अब तक १५,००० से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। देश का आंकड़ा लाखों में है। इन आंकड़ों को देखकर प्रधानमंत्री मोदी एक दिन भी सत्ता में नहीं रह पाएंगे। भारत के गरीब लोगों की ओकात अब कीड़े-मकोड़े जितनी भी नहीं रही। गरीबों को इलाज के अभाव में सड़कों और अस्पतालों की सीढ़ियों पर मरना पड़ता है।

किडनी की पथरी कैसे बनती है? जानिए 5 घरेलू आदतें जो बन सकती हैं वजह

किडनी की पथरी एक आम लेकिन बेहद तकलीफदेह समस्या है जो आजकल किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है. यह तब बनती है जब यूरिन (मूत्र) में मौजूद खनिज और एसिड साल्ट्स एक-दूसरे के साथ मिलकर छोटे-छोटे कण या क्रिस्टल बना लेते हैं. फिर ये धीरे-धीरे बढ़कर पथर का रूप ले लेते हैं. कई बार ये पथरियां खुद ही यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाती हैं लेकिन कुछ मामलों में ये मूत्र मार्ग को ब्लॉक कर देती हैं और तेज दर्द, ब्लड पेशाब और उल्टी जैसी समस्याएं पैदा कर देती हैं.

यह धीरे-धीरे बनती है और इसकी जड़ें हमारी जीवनशैली और खानपान में होती हैं. अगर समय रहते पानी सही मात्रा में पिया जाए, संतुलित भोजन लिया जाए और शरीर की जरूरतों का ध्यान रखा जाए, तो इस तकलीफदेह स्थिति से बचा जा सकता है. कुछ छोटी-छोटी घरेलू आदतें हैं जो हम ध्यान नहीं रखते. इन्हें ध्यान में रखना इसलिए भी जरूरी है ताकि किडनी की समस्या का समय रहते पता चले और सही इलाज हो सके.

इन कारणों से किडनी में बनती है पथरी
सफ़दरजंग अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग में डॉ हिमांशु वर्मा ने किडनी में पथरी के कुछ कारणों के बारे में बताया है

पानी कम पीना
सबसे पहली और सबसे आम आदत है पानी कम पीना. शरीर को डिहाइड्रेशन रखने और यूरिन को पतला रखने के लिए पर्याप्त पानी जरूरी होता है. जब शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो यूरिन गाढ़ा होने लगता है और उसमें मौजूद खनिज आपस में चिपकने लगते हैं जिससे पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है.
नमकीन खाना खाना
दूसरी आदत है बार-बार नमक या बहुत ज्यादा नमकीन खाना खाना. अधिक नमक का सेवन शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ा देता है जिससे कैल्शियम यूरिन में ज्यादा निकलता है. यह कैल्शियम पथरी बनने में मदद करता है.

बहुत ज्यादा ऑक्सालेट युक्त चीजें खाना
तीसरी आदत है बहुत ज्यादा ऑक्सालेट युक्त चीजें जैसे पालक, चाय, किडनी, बीट रूट आदि का सेवन करना. ये खाद्य पदार्थ यूरिन में ऑक्सालेट की मात्रा बढ़ा सकते हैं जो कैल्शियम के साथ मिलकर किडनी स्टोन बना सकता है.

ललित गर्ग

दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों में हिन्दी विरोध की राजनीति अब महाराष्ट्र में भी उग्र से उग्रतर हो गयी, इसी के कारण त्रिभाषा नीति को महाराष्ट्र में लगा झटका दुखद और अफसोसजनक है। आखिरकार राजनीतिक दबाव, लंबी रस्साकशी और कसमकश के बाद महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई से जुड़े मुद्दे पर यू-टर्न लेते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए। विदित हो कि केन्द्र सरकार की नीति के तहत महाराष्ट्र के स्कूलों में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना था। राजनीतिक आग्रहों एवं दुराग्रहों के चलते अब ऐसा नहीं हो पाएगा। मतलब, महाराष्ट्र को तीसरी भाषा के रूप में भी हिंदी मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र में हिंदी का संकट वास्तव में एक गहरे सामाजिक-राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। यह केवल भाषाई नहीं, बल्कि अस्मिता, पहचान और सह-अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। जबकि भाषा को संघर्ष का नहीं, सेतु का माध्यम बनाना चाहिए। क्योंकि जब मराठी और हिंदी एक-दूसरे की सहयोगी बनेंगी, तभी महाराष्ट्र और भारत दोनों का भविष्य उज्ज्वल होगा और तभी महाराष्ट्र राष्ट्रीयता से जुड़ते हुए समग्र विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा।

हिन्दी को हथियार बनाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी समर्थक राजनीति को इस तरह से गरमा दिया था कि सरकारी प्रयासों के हाथ-पांव फूलने लगे और अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना पड़ा। ठाकरे बंधुओं का हिन्दी

विरोधी आंदोलन दिनोंदिन उग्र होता जा रहा था। यह सच है, हर राज्य के लिए भाषा की राजनीति मायने रखती है और कोई भी पार्टी स्थानीय स्तर पर अपनी क्षेत्रीय भाषा से मुंह नहीं मोड़ सकती। यह सर्वविदित है कि महाराष्ट्र में पूर्व में एक समिति ने जब हिंदी पढ़ाने की सिफारिश की थी, तब उद्धव ठाकरे ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। तब हिंदी का मामला बड़ा नहीं था, पर आज जब ठाकरे विपक्ष में हैं, तब यही मुद्दा सबसे अहम हो गया है। शायद यह शर्म की बात है कि जिस राज्य की राजधानी में पूरा हिंदी फिल्म उद्योग बसता है, समूचे देश की आर्थिक राजधानी होने का गौरव जिसे मिला हुआ है, जहां समूचे देश के लोगों बसे है, जिसे सांझा-संस्कृति का गौरव प्राप्त है, उस राज्य की राजनीति अब हिंदी से परहेज करती दिख रही है। आज उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सरकार मराठी मातुप की शक्ति से हार गई, पर वे इस बात को छिपा रहे हैं कि हारी सरकार नहीं, बल्कि राष्ट्र-भाषा हिंदी हारी है, जिसने मुंबई को सपनों का शहर बनाए रखा है।

भारत विविधताओं का देश है, यहां भाषाएं न केवल संवाद का माध्यम हैं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी हैं। परंतु जब भाषाएं टकराव का विषय बन जाएं, तो वह केवल भाषाई संकट नहीं रह जाता, बल्कि एक सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दा बन जाता है। ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जहां हिंदी भाषा को लेकर एक अनकहा-अनचाहा-सा संघर्ष चल रहा है। महाराष्ट्र में



मराठी भाषा केवल एक भाषा नहीं, बल्कि मराठी अस्मिता का प्रतीक है। कई मराठी संगठनों और राजनीतिक दलों का यह मानना है कि हिंदी भाषा का बढ़ता वर्चस्व मराठी संस्कृति के लिए खतरा बन सकता है। फडणवीस सरकार को ताजा घोषणा यह दर्शा रही है कि हिंदी का मुद्दा राज्य में विपक्षी दलों के हाथों का एक ताकतवर राजनीतिक हथियार बनता जा रहा था। न केवल विपक्ष के सभी दल इस मसले पर एकजुट और विधानसभा के मॉनसून सत्र को हंगामेदार बनाने पर आमादा थे, बल्कि ठाकरे बंधुओं को भी हिंदी विरोध की राजनीति की अपनी जानी-पहचानी जमीन वापस मिलती दिख रही थी। क्योंकि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के शुरुआती दौर में पार्टी खास तौर पर हिंदीभाषियों के विरोध के लिए जानी जाती थी। मुंबई और महाराष्ट्र में हिंदीभाषियों को निरंतर बढ़ती आबादी को शिवसेना मराठी अस्मिता के लिए खतरे के रूप में देखती थी। हालांकि बाद के दौर में, खासकर नब्बे के दशक से भाजपा के गठबंधन में शिवसेना की राजनीति भी हिंदी से हिंदू की ओर मुड़ती

गई। ऐसे में निश्चित ही मराठा राजनीति से हिन्दी विरोध की उम्मीद नहीं थी। अब तक तमिलनाडु को ही हिंदी विरोध के साथ ही, महाराष्ट्र भी शामिल हो गया है। दुनिया की सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली हिन्दी भाषा अपने ही देश में उपेक्षा एवं राजनीति की शिकार है। अब केन्द्र सरकार के साथ-साथ हिंदी समाज को ज्यादा सजग होना पड़ेगा। हिन्दी भाषी प्रांतों की अपनी राजनीतिक व आर्थिक शक्ति को इतना बल देना पड़ेगा कि कम से कम तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अहिंदीभाषी राज्यों में स्वीकार किया जाए। क्या हिंदी प्रदेश के नेता इससे सवक लेंगे? हालांकि, जिस तरह की त्रासद भाषा-राजनीति महाराष्ट्र में हो रही है, उससे यही लगता है कि इसके लिये बनी समितियों में बैठने वाले विशेषज्ञों की राय को किनारे कर दिया जाएगा और राष्ट्रीयता पर क्षेत्रीयता की जीत हासिल हो जाएगी। महाराष्ट्र में बढ़ते हिन्दीभाषियों के अनुपात को देखते हुए देर-सबेर हिन्दी को अपनाना ही लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है। चाहे मुंबई हो या महाराष्ट्र,

कुल आबादी में हिंदीभाषियों का बढ़ता अनुपात हिन्दी के पक्ष में है। 2001 की जनगणना के मुताबिक हिंदीभाषियों की संख्या मुंबई में 25.9 प्रतिशत और मराठीभाषियों की 42.9 प्रतिशत थी जो 2011 में क्रमशः 30.2 प्रतिशत और 41 प्रतिशत हो गई। महाराष्ट्र में इसी अवधि में जहां मराठीभाषी आबादी 76 प्रतिशत से 73.4 प्रतिशत पर आ गई, वहीं हिंदीभाषियों का अनुपात 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 9.5 प्रतिशत हो गया। इसीलिये हिंदी लाने के इस फैसले ने न केवल उद्धव और राज ठाकरे को आक्रामक रूप में सामने ले आई बल्कि 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे के एक मंच पर आने की खबर ने महाराष्ट्र को सियासत में हलचल मचा दी। 5 जुलाई को होने वाली हिन्दी विजय रैली पर महाराष्ट्र के लोगों की निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि मराठी भाषा और संस्कृति के मुद्दे पर सूर में सूर मिलाने वाले उद्धव और राज ठाकरे को सियासी हौसला मिल गया है। जिसे महाराष्ट्र की सियासत में एक नया मोड़ माना जा रहा, लेकिन साथ ही सवाल है कि उद्धव और राज ठाकरे की सियासी केमिस्ट्री कब तक बरकरार रहेगी। हिंदी बनाम मराठी विवाद को कई बार राजनीतिक रंग भी दिया गया है। कुछ स्थानीय दलों ने हिंदी भाषी प्रवासियों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को निशाने पर लेकर हिंदी भाषा पर पक्षीय रूप से प्रहार किया है। इससे न केवल भाषा के नाम पर लोगों में दूरी बढ़ी है, बल्कि महाराष्ट्र की समावेशी छवि को भी आघात पहुंचा है। महाराष्ट्र के कई

क्षेत्रों, विशेषकर मुंबई, ठाणे, पुणे, और नासिक में बड़ी संख्या में हिंदीभाषी समुदाय निवास करता है। ये लोग महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था, व्यापार, निर्माण और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंतु जब इनकी भाषा को दोयम दर्जे का माना जाता है, या उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो यह संविधान की आत्मा ह्रापकता में अनेकताह्व के विपरीत है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी और मराठी दोनों को मान्यता प्राप्त है। हिंदी भारत की राजभाषा है और मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा। किसी भी राज्य में भाषा का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसके नाम पर दूसरी भाषाओं को अंगमार्जित करना न तो संवैधानिक है और न ही नैतिक। भाषायी सह-अस्तित्व के लिये महाराष्ट्र में मराठी, हिंदी और अंग्रेजी- तीनों भाषाओं को समुचित महत्व देकर बच्चों में बहुभाषिक दृष्टिकोण विकसित किया जा सकता है। विभिन्न राजनीतिक दल भाजपा एवं केन्द्र सरकार को घेरने के लिये जिस तरह भाषा, धर्म एवं जातियता को लेकर आक्रामक रवैया अपनाते हुए देश में अशांति, अराजकता एवं नफरत को फैला रहे रहे हैं, यह चिन्ताजनक है। महाराष्ट्र में हिन्दी का विरोध आश्चर्यकारी है। आजादी के अमृतकाल तक पहुंचने के बावजूद हिन्दी को उसका उचित स्थान न मिलना विडम्बना एवं दुर्भाग्यपूर्ण है।

क्या ये हेटस्पीच नहीं है

रविवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक रैली आयोजित की गई। इमारत-ए-शरिया फुलवारी शरीफ की ओर से आयोजित इस रैली में आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू समेत सभी दलों के बड़े नेताओं को बुलाया गया था। इस रैली में इंडिया गठबंधन के दल शरीक हुए। जिसमें बिहार में नेता प्रतिपक्ष राजद नेता तेजस्वी यादव के भाषण की खूब चर्चा हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान की सरजमाँ का हर एक-एक इंच, हर पन्ना चीख-चीखकर इस बात की गवाही देता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई सब लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया है। ये देश किसी के बाप का देश नहीं है। ये हम सब का देश है। वक्फ संशोधन कानून लाकर किस तरह मस्जिदों, मंदिरों, कग्राहों की जमीन को छीनने की योजना बनाई जा रही है, इसका खुलासा तेजस्वी ने किया और इसमें जमीन के बाद वोट छीनने की चालाकी के बारे में भी जनता को आगाह किया। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो फैसला लिया गया है, उसमें यह आशंका बढ़ रही है कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे। अगर चुनाव आयोग यह कदम पहले उठाता, तब बात दूसरी होती, लेकिन चुनाव से चंद महीने पहले ही उसे मतदाताओं की जांच की जरूरत क्यों पड़ी, पिछले साल चुनाव का से पहले इस बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया



गया, ये सारे सवाल अब उठ रहे हैं। अवैध मतदाता, बांग्लादेशी घुसपैटिए इन शब्दों की आड़ में कहीं गरीबों, पिछड़ों के वोट का अधिकार तो नहीं छीना जा रहा है, यह सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि अपने साथ-साथ अपने माता-पिता का जन्म प्रमाणपत्र या अन्य पहचान वाले दस्तावेज जुटाना साधारण, गरीब आदमी के लिए आसान नहीं होगा। फिर चुनाव आयोग क्यों इस मुश्किल को खड़ा कर रहा है, यह विपक्ष की बड़ी आपत्ति है। जब गांधी मैदान में वक्फ संशोधन कानून के विरोध के लिए लोग जुटे तो तेजस्वी यादव ने इस बारे में भी कहा कि आपकी जमीन को छीना जा रहा है। अब भाजपा सत्ता से जाने वाली है तो हम सब के गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित सब लोगों के वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। मतदाता सूची में संशोधन के नाम पर आपके वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए

आप लोग सचेत रहियेगा और ऐसा होने मत दीजिएगा। भाजपा को उम्मीद नहीं होगी कि इस मंच का इस्तेमाल अब उसके बाकी फैसलों के विरोध के लिए भी हो सकता है। हालांकि अब तो भाजपा का जो नुकसान होना है, वो हो चुका है। अब इसकी भरपाई के लिए भाजपा ने कोशिशें शुरू कर दी हैं और इस चक्कर में फिर एक गलती कर दी है। दरअसल रविवार को तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान दावा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे इस बिल को प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे और कूड़ेदान में फेंक देंगे। इस बात को भाजपा संविधान और संसद का अपमान बता रही है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 'अभी हाल ही में हमने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे दुर्दांत काले अध्याय आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण किए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि पटना के उसी गांधी मैदान में जहां आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा और संविधान के

सम्मान के लिए जान की परवाह किए बिना लाखों लोग एकत्र हुए थे, वहां एक ऐसी रैली हुई, जिसमें इंडिया गठबंधन के सहयोगी बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि संसद के कानून को (वक्फ बोर्ड कानून) कूड़ेदान में फेंक देंगे, जबकि यह कानून (वक्फ बोर्ड कानून) दोनों सदनों से पारित है और कोर्ट में विचाराधीन है। इसका अर्थ ये हुआ कि न संसद का सम्मान न न्यायपालिका का सम्मान।' श्री त्रिवेदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि वक्फ समाजवाद के विचार के खिलाफ है। उनका विचार संविधान को नीचा दिखाना, उसे तोड़ना है। वे गरीब मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि उन चंद लोगों के साथ खड़े हैं जो सारी संपत्तियों पर कब्जा करना चाहते हैं। यह समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है।' अहमरुद्दौ फीर्ी - चुनाव आयोग पर फिर सवाल चूँकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अक्सर ऐसे गंभीर विषयों पर चुप लाग जाते हैं, या फिर देर से बोलते हैं और अगर बोलते हैं तो उनमें ठोस तर्कों की जगह खोखली बातें ज्यादा होती हैं, इसलिए फिलहाल सुधांशु त्रिवेदी के वक्तव्य को ही पार्टी का आधिकारिक स्टैंड कहा जाएगा। वक्फ संशोधन कानून का विरोध भाजपा की निगाह में अगर संविधान, संसद, न्यायपालिका सबका अपमान है, तो फिर तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का जो फैसला नरेन्द्र मोदी ने लिया था, क्या उसे भी भाजपा संसद का अपमान ही कहेगी, क्योंकि कृषि विधेयक भी संसद के दोनों सदनों से पारित होकर ही कानून बने थे। लेकिन किसानों के एक साल से ज्यादा वक्त

तक चले आंदोलन के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें वापस लेने का ऐलान किया था और कहा था कि मेरी ही तपस्या में कोई कमी रही होगी। जब कृषि कानून निरस्त हो सकते हैं, तो वक्फ संशोधन कानून भी वापस लिया जा सकता है। दूसरी बात जिस तरह समाजवाद और नमाजवाद की तुक सुधांशु त्रिवेदी ने मिलाई है, क्या उसे नफरती भाषण की तरह नहीं समझा जाना चाहिए, यह बड़ा सवाल है। अहमरुद्दौ फीर्ी - ट्रंप और नेतन्याहू ईरान के आगे झुके लोकतंत्र में न समाजवाद पर किसी को आपत्ति करने का हक है, न किसी के नमाज पढ़ने, पूजा करने, या अपनी मर्जी के धार्मिक स्थल जाने या न जाने पर कोई सवाल उठा सकता है। लेकिन भाजपा के जिस तरह समाजवाद नहीं बल्कि नमाजवाद है, कहा है, उसमें नमाज पढ़ने को गलत, गैरकानूनी, अनैतिक बताने की परोक्ष कोशिश भाजपा की तरफ से दिखाई दे रही है। नमाजवाद वैसे तो ईसाई शब्द है नहीं, न ही हो सकता है। जब हम प्रार्थनावाद, पूजावाद, हवनवाद, जगदाद नहीं कहते हैं, तो फिर नमाजवाद कैसे कह सकते हैं। लेकिन भाजपा प्रवक्ता ने इस अनर्गल शब्द के जरिए एक प्रार्थना पद्धति को अपमानित किया है, जो सरासर गलत है और इस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपना पक्ष रखना चाहिए कि क्या वह भी इससे सहमत हैं। इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत से हड़बड़ाई भाजपा अपना पक्ष मजबूत करने की जगह ऐसे बयानों से और कमजोर होगी, यह बात पार्टी नेतृत्व को समझना चाहिए।

सुरक्षित हवाई यात्रा के लिए बने नयी त्ववस्था

प्रभु चावला
12 जून को 230 सवारियों वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 ने अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरी. तीस सेकंड बाद बोईंग 787-8 ड्रीमलाइनर एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल पर गिर पड़ा. उस हादसे को रोका जा सकता था. दुर्घटना ने उस विमान की बदहाली की पोल तो खोली ही, विमानन क्षेत्र से जुड़े पूरे तंत्र में व्याप्त सड़ांध की भी उजागर कर दिया. किसी भी लोकतंत्र में ऐसे हादसे जागने का अवसर होते हैं. लेकिन भारत में ऐसा नहीं है. इसके बजाय मृतकों के शोकाकुल परिवार जन शवों की तसवीरों और अनुत्तरित प्रश्नों के साथ एक से दूसरे मुर्दाघर में दौड़ रहे थे. संकट के समय मदद करने के लिए कोई टीम नहीं थी. शायद ही केंद्रीय स्तर की कोई हेल्पलाइन थी, जबकि उसका होना अनिवार्य था.

एयरलाइंस द्वारा हत्या करके बच निकलने का मुख्य कारण यह है कि उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए कोई विनियामक नहीं है. सच तो यह है कि वह कोई हादसा नहीं था. यह दैनंदिन अक्षमता के वेश में सुनिर्गोषित लापरवाही थी. भारत का विमानन क्षेत्र ऊंची उड़ान नहीं भर रहा, यह विनियंत्रण के स्तर पर डरे होने, कॉर्रपोरेट लालच और राजनीतिक उदासीनता का मिला-जुला रूप है. नतीजतन रनवे पर, हवा में और जितनेतराव लोगों के हाथों में-सर्वत्र खून है. दो कंपनियों के नियंत्रण वाला विमानन क्षेत्र सिर्फ एयरलाइंस का संचालन नहीं कर रहा, लोगों के मुताबिक, 35,000 फीट की ऊंचाई पर यह उगाही का तंत्र चलाता है. इन दो प्रमुख एयरलाइन समूहों का भारतीय आकाश के 88.5 फीसदी हिस्से पर कब्जा है. विमानों के किराये का नमूना

देखिये : दिल्ली-चंडीगढ़ के बीच 50 मिण्ट की उड़ान के 8,500 रुपये, चेन्नई से कोयंबटूर के लिए 10,200 रुपये. पिछले साल इंडिगो ने 11.8 करोड़ मुसाफिरों को गंतव्य तक पहुंचाया और 7,258 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. एयर इंडिया हिसाब-किताब के मामले में शालीनता दिखाती है, लेकिन एक बार में 470 विमानों के ऑर्डर देने का फैसला उसकी ताकत के बारे में बताता है. गो फस्ट के खत हो जाने और स्पाइसजेट की हिस्सेदारी घटकर चार फीसदी रह जाने के बाद भारतीय विमानन क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है-क्षिप्ट कॉर्टेल पुंजीवाद है.और विनियामक? जरा रुकिए, भारत में कोई विनियामक नहीं है. यहां डीजीसीए यानी नागर विमान महाविदेशालय है. नागर विमानन के लिए डीजीसीए का होना वैसा ही है,

जैसे चाकू की जगह दूधपिक्त हो. भारत का तथाकथित विमानन विनियामक फंड और संसाधन की कमी के साथ राजनीतिक अंकुश से जूझ रहा है. इसमें 53 फीसदी पद खाली हैं, जबकि संसाधनों में 91 फीसदी कटौती की गयी है. नींद से जागकर 24 जून को उसने जो जांच रिपोर्ट जारी की, वह डरावने उपन्यास की तरह लगता था. उसने रिपोर्ट में व्यवहार के अयोग्य बैगैज ट्रॉली, गलत ढंग से रखे लाइफ वेस्ट्स, रखरखाव के प्रोटोकॉल की अनदेखी, लगातार होने वाली तकनीकी चूक आदि का जिक्र किया है. डीजीसीए ने इन कमियों पर क्या रुख दिखाया? उसने एक प्रेस रिलीज जारी की, अपनी पीठ थपथपायी, फिर लंबी नींद में सो गया. भारत बड़े विमानन बाजार वाला इकलौता देश है, जिसके पास वैधानिक रूप से और स्वतंत्र विनियामक नहीं है. ब्रिटेन,

ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और पड़ोसी नेपाल तक में ऐसे स्वतंत्र निकाय हैं, जिन्हें विमानों पर उड़ान प्रतिबंध लगाने, जुमाना लगाने, यात्री अधिकारों को लागू करने, यहां तक कि अधिकारियों को जेल में डालने के लिए भी मंत्रियों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ती. अमेरिका के संघीय विमानन प्राधिकरण (एफएए) में 45,000 कर्मचारी हैं और उसका 20 अरब डॉलर का सालाना बजट है. भारत में डीजीसीए समय पर हादसे की रिपोर्ट जारी कर दे, तो यही बहुत है.

दूसरे देशों में विमान दुर्घटनाओं के बाद सुधार लागू होते हैं. वर्ष 2008 के स्पेनएयर हादसे के बाद यूरोपीय संघ ने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया. वर्ष 2018-19 में 737 मैक्स हादसे के बाद एफएए ने बोईंग जेट्स पर 20

महीने का उड़ान प्रतिबंध लगाने के साथ बदलाव भी किये. वर्ष 2023 में विमान के इंजनों का मुद्दा सामने आने के बाद ऑस्ट्रेलिया का सीएएएसए हरकत में आया. जापान में इसी साल टोक्यो के रनवे में हुई टक्कर के तुरंत बाद जेटोएसबी सक्रिय हो गया. अपने यहां अहमदाबाद विमान हादसे के दो सप्ताह बाद तक डीजीसीए चुप रहा. भारतीय विमानन क्षेत्र में सिर्फ फेयर मीटर ही तेज दौड़ता है. हां, हमारे यहां एयरपोर्ट बवालौदी के लिए विनियामक है, क्योंकि रनवे के टाइल्स यात्रियों के जीवन से ज्यादा महत्व रखते हैं. विगत मार्च में कोलकाता से दिल्ली जा रही इंडिगो की एक उड़ान को खराब मौसम के कारण जब जयपुर में उतारा गया, तो एक यात्री प्रिया शर्मा अपने पिता के अंतिम संस्कार में उपस्थित नहीं हो सकी.

राजा चौधरी ने

श्वेता तिवारी

को कहा अनपढ़, बेटी पलक की पढ़ाई पर भी किया बड़ा खुलासा

श्वेता तिवारी टीवी के दुनिया का जाना माना नाम हैं, वो काफी वक्त से इंजस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही साथ एक्ट्रेस हमेशा ही अपने पर्सनल लाइफ को लेकर लोगों के बीच चर्चा में घिरी रहती हैं. एक बार फिर उनके एक्स हसबैंड ने श्वेता के साथ अपने रिश्ते के बारे में और भी बाकी चीजों को लेकर बात की है. दोनों ने साल 1998 में शादी की थी, लेकिन दोनों की शादी ज्यादा दिन सही नहीं चली थी, जिसके बाद दोनों अलग हो गए.श्वेता तिवारी ने दो शादियां की था, जिसमें से पहली शादी उन्होंने राजा चौधरी के साथ की थी. लेकिन, बाद में कई तरह की परेशानियों के चलते वो अलग हो गए. हाल ही में राजा ने एक इंटरव्यू में उनके साथ रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा कि वो श्वेता से कई चीजों के बारे में सवाल करना चाहते हैं, जिनमें से एक ये है कि उन्होंने पुराने वक्त में पुलिस को बुलाने की जगह आपस में मामला सुलझाने के बारे में क्यों नहीं सोचा. साथ ही उन्होंने खुलासा करते हुए ये भी कहा कि श्वेता के दोस्तों ने शादी तोड़ने में



एक्ट्रेस की काफी हेल्प की. **श्वेता की कमाई थी ज्यादा** हिंदी रश से बात करते हुए राजा ने एक्ट्रेस की कमाई को लेकर बात की. उन्होंने कहा, श्वेता, मुझसे ज्यादा कमा रही थी, मैं भी काम कर रहा था, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ता है ? एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी कमाता है जिस दिन एक औरत कमाती है, उसे लगता है कि यह उसका पैसा था. लेकिन, आदमी तो कभी नहीं कहता कि यह मेरा पैसा है. औरत का पैसा औरत का पैसा होगा, अजीब नाटक है. फिर बातें होंगी कि कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, बराबरी करेंगे, अबे कहां हो बराबरी के लायक ? चार रुपए देखकर तुम्हारी नीयत बदल गई. **पलक के फ्यूचर की प्लानिंग** राजा ने बात करते हुए श्वेता की पढ़ाई को लेकर भी बात की है. उन्होंने कहा कि श्वेता ने खुद पढ़ाई नहीं की थी, इसी वजह से उन्होंने ही पलक के फ्यूचर की पूरी प्लानिंग की थी और कहा था, तुमने पैसे देखे नहीं, बचपन से तुमने गरीबी की जिंदगी जी है, चावल में रह रहे हो, अचानक से जब पैसे आए तो दिमाग खराब होता है लोगों का. पढ़ाई-लिखाई तुमने की नहीं है, अनपढ़ तुम कैसे हो, झूठे हो.

सभी कितने असहज...

वरुण धवन

ने निधन पर कवरेज को लेकर साधा निशाना, की खास अपील

एक्टर वरुण धवन एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें बेहद कम मीकों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए देखा जाता है. हाल ही में उन्होंने निधन को लेकर होने वाली मीडिया कवरेज पर अपने विचार व्यक्त किए हैं. उन्होंने बताया है कि ये कुछ लोगों के लिए कितना अनकन्फर्टेबल हो जाता है. एक्टर का ये रिएक्शन तब आया है जब हाल ही में 'कांटा लगा गर्ल' के नाम से मशहूर एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया. सोशल मीडिया पर उनके अंतिम संस्कार के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं जिसमें उनके करीबी रोते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि वरुण ने अपनी पोस्ट में किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया है लेकिन उन्होंने पयूतुरल पर होने वाली कवरेज को लेकर एक बड़ी अपील की है.वरुण धवन ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा- 'एक बार फिर से मीडिया ने किसी के निधन पर बहुत असंवेदनशील कवरेज की है. मुझे नहीं समझ में आता है कि किसी के दुख और शोक को हम लोग क्यों कवर करते हैं. वो कितने असहस लग रहे हैं. इससे भला किसी को क्या फायदा मिलता होगा. मैं मीडिया इंडस्ट्री के अपने साथियों से ये विनती करता हूं कि कोई भी अपनी अंतिम यात्रा को इस तरह कवर होते हुए नहीं देखना चाहता होगा.' उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ



ब्रोकन हार्ट इमोजी भी शेयर किया. उनकी पोस्ट से साफ पता चल रहा था कि वे कितने मायूस नजर आ रहे हैं.

सलमान खान के बिग बॉस का थीं हिस्सा

शेफाली जरीवाला की बात करें तो वे साल 2002 में कांटा लगा गाने से चर्चा में आई थीं और रातोंरात सेंसेशन बन गई थीं. उन्होंने फिल्मों और टीवी शोज में भी काम किया. वे सलमान खान के शो बिग बॉस के 13वें सीजन का भी हिस्सा रही थीं. शेफाली की पॉपुलैरिटी यूथ के बीच बहुत ज्यादा थी और उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी. उनके निधन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री काफी दुखी है.

किन फिल्मों का हिस्सा हैं वरुण धवन ?

वरुण धवन की बात करें तो वे साल 2024 में स्त्री 2 और बेबी जॉन जैसी फिल्म में नजर आए थे. बेबी जॉन फिल्म से फैस को काफी उम्मीदें थीं लेकिन ये फिल्म उम्मीद के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सकी थी. फिलहाल एक्टर 3 प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं. वे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, है जवानी तो इश्क होना है और बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों का हिस्सा हैं.



पहली ही फिल्म थी ब्लॉकबस्टर, फिर इस एक्टर ने साइन कर ली थीं 49 फिल्में



साल 1990 में एक फिल्म आई थी 'आशिकी'. इस पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस के साथ ही लोगों के दिलों पर भी राज किया और इस कदर ब्लॉकबस्टर हुई कि आज 35 साल बाद भी लोग इसे बड़े चाव के साथ देखना पसंद करते हैं. फिल्म तो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर निकली ही, वहीं इसके गानों ने भी फैस को दीवाना बना लिया था. वहीं फिल्म के लीड हीरो राहुल रॉय भी छा गए थे. राहुल रॉय की ये पहली ही फिल्म थी. डेब्यू से ही राहुल रॉय रातोंरात स्टार बन गए थे. इसके बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई थी. आशिकी के बाद उन्होंने दस-बीस नहीं बल्कि करीब 50 फिल्में साइन कर ली थीं. ये खुलासा खुद राहुल ने एक बातचीत के दौरान किया था. लेकिन इसके बावजूद राहुल फिर कभी आशिकी जैसा जादू बड़े पर्दे पर नहीं दोहरा सके. उन्हें आधी फिल्में तो छोड़नी पड़ गई थीं.

राहुल रॉय ने साइन की थीं 49 फिल्में

एक बार राहुल रॉय आशिकी का कास्ट के साथ मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो पर पहुंचे थे तब कपिल ने राहुल से सवाल किया था, **आशिकी** के बाद आपने 50 फिल्में साइन की थी ये अफवाह है या सच है ?**आ** इस पर राहुल ने कहा था, **आ**अफवाह है. लेकिन 49 फिल्में थीं और उस समय एक कानून बना था कि एक आर्टिस्ट एक साथ 12 फिल्मों से ज्यादा साइन नहीं कर सकता. मैं तो उन लकीरों को पार कर चुका था, लेकिन 25 या 26 फिल्मों के मैंने साइनिंग वापस दे दिए थे.**आ** राहुल के पास एक साथ इतनी फिल्में थीं तो उनके पास ज्यादा वर्कलोड था, ऐसे में उन्हें कई फिल्में छोड़नी पड़ी. इनमें एक फिल्म शाहरुख खान और सनी देओल की डर (1993) भी थी.

राहुल का फिल्मी करियर

आशिकी के बाद राहुल ने कई फिल्में की, लेकिन वो स्टारडम और वो शोहरत फिर कभी नहीं मिली जो आशिकी ने दिलाई थी. पहली ही फिल्म ब्लॉकबस्टर होने के बाद भी राहुल का करियर ढलान पर चला गया और वो फ्लॉप एक्टर्स में गिने जाने लगे. उन्होंने अपने करियर में 'जुनून', 'फिर तेरी कहानी याद आई', 'नसीब', 'एलान' और 'कैबरे' सहित कई फिल्मों में काम किया. राहुल मशहूर रियलिटी शो 'बिग बॉस' के पहले सीजन का खिताब भी जीत चुके हैं.

अब्बा डब्बा जब्बा कहकर ऑडियंस को हंसाने वाली ये एक्ट्रेस अब कहां है? की 100 से ज्यादा फिल्में



बॉलीवुड में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जो सुपरडुपर हिट हुए. ऐसे कई सारे डायलॉग्स भी हैं जो अपने समय में भी खूब चले और आज भी पसंद किए जाते हैं. कई कलाकारों पर तो उनके किरदार इतने भारी पड़े कि वे अपने किरदारों के नाम से ही पुकारे जाने लग गए. आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने सिर्फ 3 शब्द बोले और लोग पेट पकड़-पकड़ कर हंसने लग गए. हम बात कर रहे हैं मशहूर कैरेक्टर एक्ट्रेस उपासना सिंह की. जुदाई फिल्म में बोला गया उनका एक डायलॉग बहुत हिट रहा था. इसके बोल थे अब्बा डब्बा जब्बा. इन 3 शब्दों से ही एक्ट्रेस ने सभी को खूब हंसाया था. आइये जानते हैं कि आजकल कहां हैं और क्या कर रही हैं उपासना सिंह.उपासना सिंह का जन्म पंजाब के होशियारपुर में हुआ था. उन्होंने अपने करियर में पंजाबी, गुजराती, हिंदी और राजस्थानी फिल्मों में काम किया. बॉलीवुड में उन्हें कॉमिक और नेगेटिव शेड्स के रोल्स ज्यादा ऑफर हुए. बाई चली ससरिए नाम की राजस्थानी फिल्म से तो उन्होंने ट्रेड सेट कर दिया था. इस फिल्म को इतना पसंद किया गया था कि ये 100 दिन से भी ज्यादा दिनों तक सिनेमाघरों में चली थी. ऐसा करने वाली राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री की ये पहली फिल्म बनी थी.

एक डायलॉग ने बदल दी जिंदगी

साल 1997 में जुदाई नाम की एक फिल्म आई थी. इस फिल्म में उपासना ने वाणि का रोल प्ले किया था. फिल्म में उनकी केमिस्ट्री जॉनी लीवर के साथ देखने को मिली थी. पूरी फिल्म में उपासना अब्बा डब्बा जब्बा नाम का तकिया कलाम बोलती हैं. जब-जब वे ऐसा बोलती हैं उनके एक्सप्रेसशन देख फैस हंसी नहीं रोक पाते हैं. आज भी ये सीन काफी एपिक माना जाता है और फैस को काफी पसंद भी आता है.

इन प्रोजेक्ट्स का रहीं हिस्सा

उन्होंने गंगा का वचन, इंसाफ की देवी, डर, कृष्णा अर्जुन, जुदाई, लोफर, सरफरोश, बादल, हमारा दिल आपके पास है, हंगामा, मुझसे शादी करोगी, हलचल, गोलमाल रिटर्न्स, गॉड तुम्सी ग्रेट हो समेत कई फिल्मों शामिल हैं. टीवी की दुनिया में उन्होंने जय हनुमान, सोनपरी, मायका, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, कामेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा शो में काम किया. उनके ह्यूमर को बहुत पसंद किया जाता रहा है. अब वे फिल्मों में पहले के मुकाबले काफी कम एक्टिव रहती हैं.

प्रोजेक्ट 17ए का स्वदेशी स्टील्थ फ़्रिगेट 'उदयगिरि' भारतीय नौसेना को सौंपा गया

नई दिल्ली/एजेंसी
प्रोजेक्ट 17ए के तहत मझगांव
डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में
बनाए जा रहे सात स्टील्थ फ़्रिगेट में
से दूसरा जहाज 'उदयगिरि'
मंगलवार को भारतीय नौसेना को
सौंप दिया गया। ये बहु-मिशन
फ़्रिगेट भारत के समुद्री हितों के क्षेत्र
में पारंपरिक और अपारंपरिक दोनों
तरह के खतरों से निपटते हुए 'ब्लू
वॉटर' वातावरण में संचालन करने
में सक्षम हैं। उदयगिरि का नाम
आंध्र प्रदेश राज्य में एक पर्वत
शृंखला के नाम पर रखा गया है।
बैटल क्रूजर स्टील्थ फीचर्स, उन्नत
हथियारों और सेंसर एवं प्लेटफॉर्म
मैनेजमेंट सिस्टम से लैस है।
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स के
अनुसार उदयगिरि को लॉन्चिंग की
तारीख से 37 महीने के रिकॉर्ड
समय में भारतीय नौसेना को सौंपा
गया है। पी-17ए जहाजों में स्टील्थ
की विशेषताएं बढ़ाई गई हैं और
इनमें अत्याधुनिक हथियार और
सेंसर लगे हैं, जो पी17 श्रेणी से
काफी बेहतर हैं। ये जहाज भारतीय
नौसेना की युद्धभौत डिजाइन ब्यूरो
में इन-हाउस डिजाइन क्षमताओं में
एक बड़ी छलांग का प्रतिनिधित्व
करते हैं। उदयगिरि अपने पूर्ववर्ती
आईएनएस उदयगिरि का आधुनिक
अवतार है। यह परियोजना सेवा में
सक्रिय शिवालिक श्रेणी (प्रोजेक्ट
17) फ़्रिगेट का अनुवर्ती है।
उदयगिरि एमडीएल, मुंबई और
जीआरएसई, कोलकाता में
निर्माणधीन सात पी17ए फ़्रिगेट्स
में से दूसरा है।
प्रोजेक्ट 7ए जहाजों का पतवार
प्रोजेक्ट 17 की तुलना में 4.54
फीसदी अधिक भू-सममितीय है।
इन जहाजों में प्रोजेक्ट 17 वर्ग की
तुलना में उन्नत चिकना और
विशेषताओं के साथ एक उन्नत
हथियार और सेंसर सूट लगाया गया है।
जहाजों को संयुक्त डीजल या
गैस मुख्य प्रणाली के साथ
कॉर्नफ गैर किया गया है, जिसमें
एक डीजल इंजन और गैस
टर्बाइन शामिल है। हथियार सूट में
सुपरसोनिक सतह से सतह पर मार
करने वाली मिसाइल प्रणाली,
मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार
करने वाली मिसाइल प्रणाली, 76
मिमी गन और 30 मिमी और
12.7 मिमी रैपिड-फायर क्लोज-
इन हथियार प्रणालियों को लगाया
गया है। भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश
में एक पर्वत शृंखला के नाम पर
जहाज का नामकरण आईएनएस
उदयगिरि के नाम पर किया गया है।

दिल्ली में आयोजित हुआ ब्राइडल कम्पटीशन एंड मेकअप सेमिनार अवॉर्ड शो, सेलिब्रिटी ऐश्वर्या शर्मा रहीं मुख्य आकर्षण



दिव्य दिल्ली: दिल्ली के जनकपुरी
स्थित SK Precious
Banquet में भव्य ब्राइडल
कम्पटीशन एंड मेकअप सेमिनार
अवॉर्ड शो का आयोजन किया
गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व और
आयोजन हर्षल रम्मन द्वारा किया
गया, जो मेकअप इंडस्ट्री में उभरते
हुए नामों को मंच देने के लिए
जाने जाते हैं। कार्यक्रम में टीवी
इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री
और 'गुम है किसी के प्यार में'
फेम ऐश्वर्या शर्मा ने बतौर
सेलिब्रिटी गेस्ट शिरकत की। उनके
आगमन से शो की रौनक और भी
बढ़ गई और प्रतिभागियों में जोश
की लहर दौड़ गई। इस विशेष
अवसर पर देशभर से आए मेकअप

आर्टिस्ट्स और मॉडल्स को एक
साझा मंच मिला, जहां
उन्होंने अपनी
कला और
प्रतिभा का
शानदार
प्रदर्शन
किया।
कार्यक्रम
का प्रमुख
आकर्षण रहा
मेकअप
एजुकेटर स्नेहा शर्मा
द्वारा दी गई लाइव मेकअप
क्लास, जिसमें उन्होंने मेकअप
आर्टिस्ट्स को नवीनतम ट्रेंड्स,
ब्राइडल लुक्स और इंडस्ट्री में
उभरती तकनीकों के बारे में

विस्तार से बताया। ब्राइडल
कम्पटीशन में प्रतिभागियों ने
पारंपरिक से लेकर मॉडर्न
दुल्हन के लुक्स को
बेहतरीन ढंग से
प्रस्तुत किया। रैम्प
वॉक के दौरान हर
मॉडल की
खूबसूरती और
मेकअप की कला ने
दर्शकों को मंत्रमुग्ध
कर दिया। कार्यक्रम के
अंत में विजेताओं की घोषणा
करते हुए सेलिब्रिटी ऐश्वर्या शर्मा
ने उन्हें सम्मानित किया। उन्हें ताज
पहनाकर और अवॉर्ड प्रदान कर
उत्साहवर्धन किया गया। विजेताओं

के चेहरे पर आत्मविश्वास और
संतोष की झलक साफ नजर आई।
हर्षल रम्मन ने कहा कि, इस प्रकार
के आयोजनों से न केवल नए
टैलेंट को मंच मिलता है, बल्कि
मेकअप इंडस्ट्री को एक प्रोफेशनल
पहचान भी मिलती है। हम देशभर
के उभरते मेकअप आर्टिस्ट्स को
एक ऐसा मंच दें जहां वे अपने
हुनर को निखार सकें। यह
आयोजन मेकअप इंडस्ट्री से जुड़े
सभी कलाकारों के लिए न केवल
एक प्रतियोगिता रहा, बल्कि एक
सीखने और नेटवर्किंग का सुनहरा
अवसर भी साबित हुआ। आने
वाले वर्षों में ऐसे और आयोजनों
की उम्मीद जताई जा रही है।



जीएसटी ऐतिहासिक सुधार: प्रधानमंत्री

नई दिल्ली/एजेंसी
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) की
आठवीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र
मोदी ने मंगलवार को कहा कि
अप्रत्यक्ष कर शासन एक ऐतिहासिक
सुधार के रूप में खड़ा है, जिसने
भारत के आर्थिक परिदृश्य को फिर
से आकार दिया है। प्रधानमंत्री ने
कहा, "अनुपालन बोझ को कम
करके इसने विशेष रूप से छोटे और
मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करने
में आसानी में बहुत सुधार किया है।"
प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट पर एक
फोटो शेयर करते हुए लिखा,
जीएसटी को लागू हुए आठ साल हो
गए हैं। यह एक ऐतिहासिक सुधार के
रूप में सामने आया है। जिसने भारत
के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार
दिया है। अनुपालन बोझ को कम



करके, इसने विशेष रूप से छोटे और
मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करने
में आसानी में बहुत सुधार किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी ने
आर्थिक विकास के लिए एक
शक्तिशाली इंजन के रूप में भी काम
किया है। इसके साथ ही भारत के
बाजार को एकीकृत करने की इस

यात्रा में राज्यों को समान भागीदार
बनाकर सच्चे सहकारी संघवाद को
बढ़ावा दिया है। जीएसटी के वर्तमान
स्ट्रक्चर में चार मुख्य स्लैब 05
फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी
और 28 फीसदी हैं। ये दरें देशभर में
अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर
लागू होती हैं। उल्लेखनीय है कि देश
में जीएसटी एक जुलाई, 2017 को
लागू हुआ था, जिसने देश की कर
प्रणाली को पूरी तरह बदल दिया है।
वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी
क्लेक्शन रिकॉर्ड 22.08 लाख
करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जो
पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.4
फीसदी की वृद्धि है। जीएसटी ने
लगभग 17 स्थानीय करों और 13
उपकरों को पांच स्तरीय ढांचे में
समाहित कर दिया है।

दिल्ली में बड़ा एवशन: सात अवैध बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

दिव्य दिल्ली : दिल्ली के उत्तर-
पश्चिम जिले से बड़ी खबर आ
रही है, जहाँ विदेशी प्रकोष्ठ की
विशेष टीम ने सात अवैध
बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार
किया है। इनमें से एक, सुहान
खान, को पहले भी 15 मई
2025 को निर्वासित किया गया
था, लेकिन वह फिर से अवैध
रूप से भारत में घुस आया। इस
गिरफ्तारी से यह साफ संदेश
जाता है कि भारत में अवैध प्रवेश
अब नहीं चलेगा। टीम ने इन
प्रवासियों के पास से तीन
स्मार्टफोन भी बरामद किए हैं,
जिनमें प्रतिबंधित वीडियो ऐप



इंस्टॉल था झ जिसका इस्तेमाल
वे बांग्लादेश में अपने परिवारों से

संपर्क के लिए कर रहे थे। यह
ऑपरेशन शालीमार बाग और

आसपास के इलाकों में चलाया
गया था और इसे बेहद
सुनियोजित और समन्वित तरीके
से अंजाम दिया गया। इस दौरान
पाँच ट्रांसजेंडर व्यक्ति, एक
महिला और एक पुरुष को भी
गिरफ्तार किया गया, जो बिना
वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे
थे। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई
न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत
करती है, बल्कि अवैध प्रवास पर
जिरो टॉलरेंस की नीति को भी
दशाती है। जांच जारी है और
सभी आरोपियों को कानूनी
प्रक्रिया के तहत आगे डीपॉर्ट
किया जाएगा।"

कर्नाटक कांग्रेस में बदलाव की अटकलों पर विराम

बंगलूरु/एजेंसी
कर्नाटक कांग्रेस में शिर्ष नेतृत्व में
बदलाव को लेकर तेज होती
अटकलों पर पार्टी के कर्नाटक
प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने एक
बार फिर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
मंगलवार को उन्होंने नेतृत्व
परिवर्तन की चर्चा को सिरे में
नकारते हुए साफ और स्पष्ट रूप से
कहा कि पार्टी इस मुद्दे पर किसी भी
तरह की राय नहीं ले रही है। उन्होंने
कहा कि वर्तमान में वे केवल

विधायकों और सांसदों से उनके
क्षेत्रों में किए गए कार्यों की
जानकारी ले रहे हैं। पत्रकारों से
बातचीत के दौरान सुरजेवाला ने
कहा कि कल भी मैंने जवाब दिया
था और आज भी साफ कर रहा हूँ।
नेतृत्व परिवर्तन को लेकर राय लेना
का सवाल ही नहीं है। जवाब
केवल एक शब्द में है नहीं। बता दें
कि सुरजेवाला ने मामले में
आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान
कही।

350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सीएम भजनलाल का रोडमैप स्पष्ट

जयपुर/एजेंसी
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि
राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की
अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को लेकर
राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है।
इसके लिए आधारभूत संरचना, कृषि,
शिक्षा और उद्योग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में
आधुनिक तकनीक और नवाचार को
बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास
पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में
उन्होंने युवाओं को रोजगारपरक बनाने,
कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस



(अक) के प्रयोग और लॉजिस्टिक्स
पार्क की स्थापना को लेकर विस्तृत
युवाओं को प्लूचर रेडी और इंडस्ट्री रेडी

बनाने के लिए सरकार उन्हें अत्याधुनिक
कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि
युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप
प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उन्हें बेहतर
रोजगार के अवसर मिल सकें। उन्होंने
बताया कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने
और किसानों की आमदनी में वृद्धि के
लिए सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सलेंस
ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन
एग्रीकल्चर की स्थापना की घोषणा की
है।

एटीएफ की कीमत में 7.5 फीसदी का हुआ इजाफा, नई दरें लागू

नई दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा ईंधन
विक्रेताओं के मुताबिक तेल एवं गैस
विपणन कंपनियों ने तीन दौर की
कटौती के बाद विमान ईंधन की
कीमतों में 7.5 फीसदी का इजाफा
किया है। इसके बाद राष्ट्रीय
राजधानी नई दिल्ली में एटीएफ की
कीमत 6,271.5 रुपये प्रति
किलोलीटर यानी 7.5 फीसदी
बढ़कर 89,344.05 रुपये प्रति

किलोलीटर हो गई है। नई दरें
मंगलवार से प्रभावी हो गई हैं। यह
वृद्धि पिछले महीने ईरान पर
इजराइल के हमले के बाद
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल
की कीमतों में आई तेजी के अनुरूप
है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई
में एटीएफ की कीमत 77,602.73
रुपये प्रति किलोलीटर से बढ़ाकर
83,549.23 रुपये प्रति
किलोलीटर पर पहुंच गई है।

कंस्टीट्यूशन क्लब में राजनीतिक की पाठशाला का भव्य स्थापना दिवस, लोकतांत्रिक चेतना के प्रसार में योगदानकर्ताओं को किया सम्मानित



दिव्य दिल्ली: दिल्ली।
कंस्टीट्यूशन क्लब में
राजनीतिक की पाठशाला का
आठवां स्थापना दिवस
कार्यक्रम भव्य रूप से

आयोजित किया गया। कार्यक्रम
का नेतृत्व संस्थापक डॉ. अजय
पांडे ने किया, जिसका
शुरूआत दीप प्रज्वलन से हुई।
इस अवसर पर मुख्य अतिथियों



के रूप में डॉ. अभिषेक वर्मा,
नरेश सिसोदिया, अशोक चौबे,
रोहित पांडे, एस.के. दुग्गल,
ए.पी. सिंह, देवेन्द्र यादव और
जितेंद्र सिंह सेंटी शामिल

रहे। डॉ. अजय पांडे द्वारा वर्ष
2017 में शुरू की गई
राजनीतिक की पाठशाला आज
हजारों लोगों को जोड़कर
देशभर में लोकतांत्रिक मूल्यों



और संवैधानिक चेतना को
मजबूत कर रही है। कार्यक्रम में
अतिथियों ने जातीय भेदभाव
और देश के विकास जैसे
अहम मुद्दों पर चर्चा की और

राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने
की इस पहल की सराहना की।
साथ ही डॉ. अजय पांडे के
कार्यों की भी प्रशंसा की। इस
अवसर पर राजनीतिक की



पाठशाला में योगदान देने वाले
लोगों और वरिष्ठ पत्रकारों को
सम्मानित कर अवॉर्ड प्रदान
किए गए। यह मंच संविधान,
लोकतंत्र और नागरिक

अधिकारों को जन-जन तक
पहुँचाने के लक्ष्य के साथ आगे
बढ़ रहा है और वर्तमान में
इसकी पहुँच देश के सभी राज्यों
तक विस्तारित हो चुकी है।